

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

2 मार्च, 1987

खण्ड 1, अंक 4

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार, 2 मार्च, 1987

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(4)1
वर्ष 1987-88 का बजट पेश करना	(4)28

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 2 मार्च, 1987

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे।

Issuance of permits to Unemployed Youths for plying Mini-Buses

***1230 Seth Ram Dass Dhamija:** Will the Minister for Transport be pleased to state wheth there is any proposal under consideration of the Government to issue permits to the Unemployed Youth for plying Mini-Buses in the state; if so the time by which a decision in the matter is likely to be taken?

Transport Minister (Shri Amar Singh): No, Sir,

सेठ राम दास धमीजा: स्पीकर साहब, आज के दिन हरियाणा में बहुत बेरोजगारी फैली हुई है। यदि लोगों को काम मिल जायेगा तो वे गलत धन्धे नहीं करेंगे क्योंकि जब लोगों को करने को कोई काम नहीं होता तो वे वे फिर इधर-उधर बेकार से घूमते रहते हैं और गलत काम करने लग जाते हैं। इसलिए यदि सरकार मिनी बस परमिट नहीं दे सकती तो कम से कम थ्री व्हीलर

के ही लोगों को परमिट जारी कर दे ताकि उनको रोजगार तो मिल सके। क्या ऐसा कोई मामला सरकार के विचाराधीन है?

श्री अमर सिंह: स्पीकर साहब, सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई मामला नहीं है। हमारे प्रदेश की नेनेलाईजेन है और सारे हिन्दुस्तान ने ट्रासपोर्ट की सबसे अच्छी सर्विस हरियाणा की ही है। जहां तक बेरोजगारी को दूर करने की बात है, सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए कई स्कीमों चलाई हुई है। इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट ने अनएम्प्लयमेंट को समाप्त करने के लिए कई स्कीमों चलाई हुई है। जिन लोगों को ये रोजगार दिलाना चाहते हैं, उनकी ऐप्लीकेशन इन विभागों में दिलवाए उनकी काम मिलेगा।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने तो मैं सवाल का जवाब न में दिया है। मैंने इसी सिलसिले में एक सवाल इससे पहले सेशन में किया था कि जिन लोगों ने बैंकों से लोन लेकर थ्री व्हीलर यादि खरीदे हुए हैं और सरकार ने जिनको भुर्रु में परमिट इस्सू किए थे, उनके परमिट जारी रखे जायें। अब सरकार ने अपना फैसला बदल दिया है जिसके कारण बहुत सारे लोग परेशान हुए फिर रहे हैं और उनके ऊपर बैंकों से लिये गए ऋण का ब्याज भी पड़ रहा है। मुझे ठीक फिगरज का तो पता नहीं लेकिन स्टेट में सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग होंगे जिन को पहले परमिट दिए गए थे। मैं सरकार से सिर्फ इतना जानना

चाहता हूँ कि जिन लोगों को पहले परमीट जारी किए गए थे, क्या उनका कोई रूट मुहैया किया जायेगा।

श्री अमर सिंह: यह ठीक है कि कुछ साल पहले फोर व्हीलर के लिए कुछ लोगों को परमीट इतने दिए गए थे लेकिन थ्री व्हीलर के लिए कोई परमीट जारी नहीं किया गया था। फोर व्हीलर में 5-6 सवारियों को बैठाने के लिए परमिट होता है लेकिन ये 5-6 सवारियों को बैठाने की बजाये उसमें 35-40 सवारियों को बैठा लेते थे जिनकी वजह से इनके आए दिन ऐक्सीडेंट्स होते रहते थे। सरकार के नोटिस में ऐसे काफी केसिस आए हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह सिलसिला बिल्कुल बंद कर दिया है।

चौधरी साहब सिंह सैनी: धमीजा साहब ने ठीक प्रश्न किया था कि बेरोजगारी की वजह से काफी यूथ बेकार में इधर-उधर घूमते रहते हैं। देहात के ऐसे काफी रूट्स हैं जहाँ पर बसें नहीं चलतीं। यदि उन रूट्स पर इन बेकार नौजवानों को परमीट दे दिया जाये तो बेकारी भी दूर हो सकेगी और लोगों को भी आने-जाने में दिक्कत नहीं होगी। क्या ऐसी किसी प्रोपोजल पर सरकार गौर करेंगी?

श्री अमर सिंह: ऐसी कोई प्रोपोजल सरकार के विचारधीन नहीं है। सरकार अपनी तरफ से 100 प्रतिशत

कोि । । करती है कि देहात का कोई लिंक रोड या ऐप्रोच रोड बिना सर्विस के न रह जाये ।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, श्री व्हीलर को भी सरकार की तरफ से परमिट इू हुए है । मेरे सकेते जिले में भी कम से कम ऐसा 14-15 परमिट इू हुए थे । अब ये बता रहे है कि ऐसे परमिट देने की इसकी पालिसी नही है । आज वे लोग यू ही उनकी चलाये फिर रहे है । पिछले सै ।न में कर्नल साहब ने आ वासन दिया था कि सैकड़ों की तादाद में जिन लोगों ने बैंकों से लोन लेकर ये श्री व्हीलर लिए हुए है, उनके लिए कोई व्यवस्था करेंगे । अब मंत्री जी ऐसे परमिट जारी करने से मना कर रहे है । क्या मंत्री जी पहले दिए हुए आ वासन को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यह बेरोजगारी को दूर करने में भी सहायक होगा और दूसरे जनहित में भी होगा?

श्री अमर सिंह: स्पीकर साहब, पहले ही यहां पर एक सवाल के जवाब में बताया जा चुका है कि हमने हरिजन कल्याण निगम, बैंकवर्ड क्लासिज कल्याण निगम, इकौनोमीकली बीकर कलासिज कल्याण निगम और राज्य सैनिक बोर्ड से पूछा है कि उन्होंने कितने-कितने लोगों को टैम्पी आदि खरीदने के लिए लोग दिया है । हमने उनको रिमाइन्डर भी दिया है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई सूचना नही भाई है । जब सूचना था जायेगी तो इस पर विचार करेंगे ।

श्री बनारसी दास बाल्मीकि: स्पीकर साहब, हजारों की तादाद में थ्री व्हीलर चल रहे हैं। वे सरकार को टोकन टैक्स आदि भी रहे हैं। यदि उन लोगों की परमीट जारी कर दिए जाए तो बेरोजगारी भी दूर होगी और सरकार को भी फायदा होगा। जिन हरिजन भाइयों ने या दूसरे लोगों ने लोन से थ्री व्हीलर लिया हुआ है, क्या उनको सरकार परमिट इ पू करेंगी?

श्री अध्यक्ष: इस का जवाब तो पहले ही दिया जा चुका है।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हरेक रूट पर बसिज जाती है। कई सड़कों पर तो बिल्कुल भी नहीं जाती। कई स्थानों पर तो बस दिन में सिर्फ एक ही चक्कर लगाती है जिसके कारण रास्ते में पड़ने वाले लोगों की काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जहाँ पर बसिज नहीं चलती, क्या वहाँ पर ऐसे परमिट जारी करने पर विचार करेंगे?

श्री अमर सिंह: स्पीकर साहब, बस का एक किलोमीटर पर 3 रूपये 10 पैसे खर्च आता है। जिन रूटों पर हमें एक किलोमीटर पर 2 रूपये भी मिल रहे हैं, वहाँ पर भी हम बसे चला रहे हैं। जहाँ से लोगों की बस चलाने की डिमांड आती है, उसको हम पूरा करते हैं। यह ठीक है कि सभी जगह 8-10 टाइम डेली

नहीं दिए जाते। हम रसीट के मुताबिक पूरी सर्विस दे रहे हैं। ये हमें बतायें कि कहां पर बसें नहीं चल रही, हम वहां भर्जेंगे।

श्री अध्यक्ष: आपकी यह बात ठीक है कि कुछ सड़को पर आपको पूरा किराया नहीं मिलता। जब हम जी० एम० से किसी रूट बस भेजने के लिए कहते हैं तो वे हमें बताते हैं कि यह वाए बेल नहीं बनता, इसलिए नहीं भेज रहे। जहां पर आपको पूरा किराया नहीं मिलता क्या वहां पर भी आप कुछ इंतजाम करेंगे?

श्री अमर सिंह: बिल्कुल करेंगे। जहां हमारा किराया पूरा नहीं होता और लोगों की डिमांड बहुत जरूरी है वहां पर लोगों की मांग को हम अवश्य मीट करने की कोशिश करेंगे।

सेठ राम दास धमीजा: हरियाणा के बॉर्डर पर राजस्थान के लोगों की काफी प्राइवेट बसिज चलती हैं। क्या उनकी बजाये हरियाणा वालों की परमीट इंतजाम करेंगे?

श्री अमर सिंह: वे राजस्थान के बॉर्डर पर चलती होंगी। हरियाणा में किसी प्राइवेट बस को बगैर परमीट के चलने की इजाजत नहीं दी जायेगी।

Construction of New Building of Community Health Centre at Barwala

***1244. Chaudhri Inder Singh Nain:** Will the Minister for Health & Ayurveada be pleased to refer to the reply to starred question No. 1122 answered on the floor of the House on 27.2.1986, and state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct new building for Community Health Centre at Barwala (Hissar): and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to materialize together with the estimated cost thereof?

स्वारथ्य मंत्री (श्री गोवर्धन दास चौहान):

(क) जी, हां।

(ख) अतिरिक्त भवन की वर्तमान अनुमानित लागत 7.64 लाख रूपये है। परन्तु भवन का पूर्ण होना जमीन तथा धन की उपलब्धि पर निर्भर करेगा।

चौधरी इन्द्र सिंह नैन: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे इस सवाल के बारे में मंत्री जी ने पहले भी आवासन दिया था कि यह बिल्डिंग बनाई जायेगी। इस आवासन को दिए हुए एक साल होने जा रहा है। मैं आपको द्वारा मंत्री मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी बनाया जाये। मैं आपके द्वारा साथ ही साथ वित्त मंत्री जी से भी प्रार्थना करूंगा कि आज वे चूंकि बजट पे 1 कर रहे हैं, इसलिए वे इस बिल्डिंग के लिए अब य पैसा रखें ताकि यह बिल्डिंग जल्दी से जल्दी बनाई जा सके।

श्री गोवर्धन दास चौहान: पैसा मिलते ही भीघ्र काम भुरु करवा दिया जायेगा।

श्री केवल सिंह: स्पीकर साहब, बरवाला से हिसार 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। उससे आगे चल कर हांसी भाहर आता है। बरवाला, हिसार और हांसी तीनों ट्रायंगल पर स्थित है। इन तीनों के बीच कोई पी० एच० सी० नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इन तीनों स्थानों में से किसी उचित जगह पर एक पी० एच० सी० जरूर खोलें।

श्री गोवर्धन दास चौहान: यह ठीक है कि इन तीनों भाहरों के बीच कोई पी० एच० सी० नहीं है लेकिन पी० एच० सी० खोलने के कुछ नार्मर्ज फिक्स किए गए हुए हैं इस इलाके की तरफ स अभी तक कोई पी० एच० सी० खोलने की मांग नहीं आई। हिसार से काफी बड़ा हस्पताल है और हांसी में भी बड़ा हस्पताल है। इसके अलावा हमने इन तीनों जगहों के बीच में कुछ हेल्थ सब सैन्टर खोले हुए हैं। जब कभी लोगों की तरफ से मांग आयेगी तो उस समय इन तीनों स्थानों के बीच कोई पी० एच० सी० खोलने पर विचार किया जा सकता है।

चौधरी कुन्दन लाल: अध्यक्ष महोदय, पिछले सैं उन के दौरान मंत्री जी ने हाउस में प्रत्येक सब-डिविजन पर पोस्ट-मौर्टस की सुविधा देने का आ वासन दिया था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ऐक्सीडैन्टस या कत्ल में जिन लोगों की डैथ हो जाती है उनका दो-दो दिन तक पोस्ट-मौर्टस नहीं होता जिसके कारण ला ं काफी सड़ जाती है और गार्मियों के दिनों में तो और भी

बुरा हालत हो जाती है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या प्रत्येक सब-डिविजन पर पोस्ट मोर्टम की सुविधा दिए जाने के आवासन को पूरा करेंगे?

श्री गोवधन दास चौहान: स्पीकर साहब, जिस सब-डिविजनल हैडक्वार्टर पर 30 बिस्तरों वाला हस्पताल है। वहाँ हम यह सुविधा देने जा रहे हैं और पोस्टमोर्टम रूम बनाये जाएंगे।

चौधरी साहब सिंह सैनी: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने अभी हिसार के बारे में जवाब दिया है। मैं इनसे कुरुक्षेत्र के बारे में एक सवाल पूछना चाहूँगा। कुरुक्षेत्र में हस्पताल है। प्राईमरी हैल्थ सैन्टर्ज रादौर, रामारण माजरा और खानपुर कोलीयान में है। इनके बीच में लाडवा पड़ता है। वहाँ कम्युनिटी हैल्थ सैन्टर खोलने के लिए केस आया हुआ है। मैं मंत्री जी से आवासन चाहता हूँ कि क्या लाडवा में कम्युनिटी हैल्थ सैन्टर जल्दी खोला जाएगा?

श्री गोवधन दास चौहान: स्पीकर साहब, पर्टिकुलर क्वैशन बरवाला के लिए था। मैं इनको देख लूँगा कि इसके लिए क्या हो सकता है।

चौधरी सूबे सिंह पूनिया: स्पीकर साहब, पिछले साल कुछ प्राईमरी हैल्थ सैन्टर्ज अपग्रेड हुए हैं और कुछ नए सब-सैन्टर्ज खुले हैं लेकिन बहुत से सब सैन्टर्ज ऐसे हैं जिनकी

बिल्डिंग तो बनी हुई है लेकिन ए0एन0एम0 की नियुक्ति नहीं हुई है। मेरे हल्के में तीन जगह ऐसी हैं। तीनों जगह बिल्डिंग ज साल, दो साल से खराब हो रही है। क्या मंत्री जी ऐसी जगहों पर ए0एन0एम0 जल्दी लगाने की कृपा करेंगे?

श्री गोवधन दास चौहान: स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने आज ही यह बात बताई है। अगर इन्होंने पहले बताया होता तो इन जगहों की रिक्वायरमेंट को हम पहले पूरा कर देते। फिर भी मैं अब इन्हें विवास दिलाता हूँ कि हम ये जगहें खाली नहीं रहने देंगे।

चौधरी सूबे सिंह पूनिया: स्पीकर साहब, मैं मिनिस्टर साहब को कमि नर साहब को और डायरेक्टर साहब को इस सम्बन्ध में पिछले एक साल में दो बार पत्र लिख चुका हूँ।

श्री गोवधन दास चौहान: स्पीकर साहब मुझे कोई पत्र नहीं मिला है।

बहिन भान्ति देवी: स्पीकर साहब, मैं भी आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि करनाल की तरफ से ये कुछ ध्यान दें। हमारे यहां ग्रिवैन्सिज कमेटी की मीटिंग में भी मिनिस्टर साहब ही आते हैं। वहां तो सबसे बड़ा ग्रिवैन्स कमेटी का ही है। वह हस्पताल 100 वर्ष पुराना, जर्जर और खराब हालत में है। लगभग तीन साल हुए जब नए हस्पताल का िालान्यास हुआ था लेकिन पैसे की कमी

की वजह से वह नहीं बन रहा है मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगी कि इस बार ये उसके लिए पूरा पैसा दें। वित्त मंत्री जी से भी मेरी प्रार्थना है कि वे इसके लिए पूरा पैसा दें। स्पीकर साहब, मजे की बात यह है कि मेरे सिवाए करनाल जिले के जितने एम0एल0एज0 हैं वे या तो मंत्री हैं या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोई भी इसके लिए सिफारिश करने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष: स्पीकर को क्या वापस बुलाना चाहती है?(हंसी) मिनिस्टर साहब, यह बात ठीक है कि काफी देर से उस हस्पताल का निर्माण हुआ पड़ा है। उसको बनाने की तरफ भी ध्यान दिया जाए।

श्री गोवधन दास चौहान: स्पीकर साहब, जैसे जैसे धन उपलब्ध होगा, हम इसकी ओर भी ध्यान देंगे।

चौधरी अजमत खां: स्पीकर साहब, सरकार की नीति है कि हर तहसील हैड क्वार्टर पर हस्पताल या पी0एच0सी0 बनाएंगे लेकिन यह हथी की बदकिस्मती है कि वहां यह सुविधा नहीं मिली है। उसे तहसील बने 7 साल अर्सा हो गया है क्या मंत्री जी वहां भी पी0एच0सी0 या सिविल हस्पताल बनवाने की कृपा करेंगे?

श्री गोवधन दास चौहान: मैं इसकी जांच करवा लूंगा कि यहां यह सुविधा क्यों नहीं है।

चौधरी कुन्दन लाल: स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने कहा कि जिस सब डिविजनल हैडक्वार्टर पर 30 बिस्तरों वाला हस्पताल होगा वहां यह सुविधा देगे। मै मंत्री जी से निवदेन करूंगा कि सफीदों मे तो 30 बिस्तरों वाले हस्पताल का उद्घाटन आपने ही किया है। इसके अलावा सफीदों से जींद 35 किलोमीटर दूर है जहां पोस्ट मॉर्टम करवाने के लिए जाने मे बहुत दिक्कत होती है। क्या मंत्री जी वि वास दिलायेगे कि कितनी जल्दी यह सुविधा वहां दे दी जाएगी?

श्री गोवधन दास चौहान: स्पीकर साहब, मै पहले ही कह चुका हूं कि सब डिविजनल हैडक्वार्टर पर हम इसका इन्तजाम करवा देंगे।

33 K. V. Grid Sub-Station at Bichpari of District Sonapat

***1256 Sh. Bhale Ram:** Will the Minister for irrigation and Power be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a 33 KV Grid Sub-Station in Bichpari Village of District Sonapat; if so, the time by which proposal is likely to materialise?

Irrigation & Power Minister (Ch. Shamsheer Singh Surjewala): Yes. The proposal is presently under consideration of the State electricity Board and is likely to materialize during the year 1987-88.

श्री भले राम: स्पीकर साहब, मै मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो 33 के0वी0 सब-स्टे ान बना रहे है, क्या

इसके लिए गांव वालो ने जमीन दे दी हैं और इससे कितने गांवो को फायदा होगा?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, इसके लिए ग्राम पंचायत ने 5 एकड़ जमीन देने की बात मान ली है और इसके प्रोजैक्ट वर्कस और डिजाईन वगैरा का काम भुरु कर दिया गया है। जल्दी ही हम इस जमीन का पोजै इन लेने वाले हैं। इस वक्त बिचपड़ी और आस पास के गावों का 11 के0वी0 सब-स्टे इन जागसी और 11 के0वी0 सब-स्टे इन बुटाना से बिजली मिल रही है और ये सब-स्अन्ज 132 के0वी0 सब-स्टे इन गोहाना से फीड हो रहे है। यह लाईन 30 किलोमीटर लम्बी है जिसकी वजह से इन गांवो मे लो वोल्टेज की प्रौब्लम है, इसलिए बिचपड़ी मे 33 के0वी0 सब-स्टे इन लगाने का प्रोग्राम है। यह सब-स्टे इन 15 लाख रूपये का लगेगा। 10 किलोमीटर लम्बी लाईन बनाई जाएगी जिस पर 7 लाख रूपया खर्च होगा। स्पीकर साहब, जल्दी ही यह काम भुरु किया जाएगा।

Setting Up of Oil Refinery in the State

***1252 Sh. Bhale Ram & Sh. Nihal Singh:** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether any communication dindicating the decision of the Government of India to set up an Oil Refinery in the State has been received by the Government ; and

(b) if so, details therof together with the time by which the above said Refinery is likely to be set up?

उधोग मंत्री (श्री श्रीकिान दास):

(क) जी हां।

(ख) भारत सरकार करनाल मे प्रतिवर्श छः मिलियन टन की क्षमता वाले तेल भाोधक कारखाने की स्थापना हेते विभिन्न विवरणों को अन्तिम संबंधित विभिन्न विवरणों को अंतिम रूप दिये जाने के बाद ही पता लग सकेगा।

श्री भले राम: क्या मंत्री जी बताएंगे कि भारत सरकार से जो पत्र आया है उसमे क्या लिखा है?

श्री श्रीकिान दास: उसमे तो यही लिखा हुआ है कि यह कारखाना लगेगा और इस पर 1500 करोड़ रुपया खर्च होगा।

श्री निहाल सिंह: क्या मंत्री जी बतायेगे कि इसके लिए कितनी जमीन दरकार होगी और साईट कहां सिलैक्ट की गई हैं?

श्री श्रीकिान दास: इसके वास्ते 2080 एकड़ 2 कनाल 10 मरले जमीन लेंगे। इसमे से 1247 एकड़ जमीन को कस्टोडियन की है और 833 एकड़ जमीन प्राईवेट आदमीयों की है। यह जमीन गांव बहौली के पास हैं।

श्री कंवल सिंह: स्पीकर साहब, हमारे प्रान्त मे यह बहुत बड़ा कारखाना लगने जा रहा हैं। पिछले सैान से आपने नोट किया होगा कि मारुती उधोग के बारे मे जिक्र आया था। वहा पर दूसरी स्टेट के लोगों को रोजगार दिया जाता है जब कि हमारी

स्टेट बिजली देती हैं और दूसरी हमारी स्टेट ने ही जमीन दी है। इसलिए क्या मंत्री महोदय केन्द्र से आग्रह करेंगे कि जितने भी रोजगार यहां निकले उनमें हरियाणावासियों को प्राथमिकता दी जाये और दूसरी स्टेट के लोगों का न दी जायें?

श्री श्रीकिान दास: हरियाणा के आदिमियों का पूरा ध्यान रखा जायेगा।

श्री भले राम: क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि इस कारखाने में लेबर की अप्वायंटमेंट भुरु कर दी है।

श्री श्रीकिान दास: अभी कोई ऐसी अप्वायंटमेंट नहीं की है।

बहिन भान्ति देवी: अध्यक्ष महोदय, इस कारखाने को लगाने की बात पांच साल से चल रही है और अब भी यही कह रहे हैं कि बात चल रही है। इस कारखाने के बारे में बात ही नहीं चलनी चाहिए बल्कि बड़ी मेहनत से, उत्साह और लग्न से इसे लगाने को काम करवाना चाहिए क्योंकि चौधरी बंसी लाल जी तो निर्माण के कामों में बड़ी रुचि लेते हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि इस कारखाने को कब तक लगवा रहे हों और कौन सी तारीख तक यह लग जायेगा?

श्री श्रीकिान दास: स्पीकर साहब, इस कारखाने को लगवाने में चौधरी बंसी लाल जी ने पर्सनल लैवल पर कोर्नर की है और इसके लिए केन्द्रीय सरकार से भी कह रहे हैं कि

जल्द से लगाया जायें। जब 21 तारीख को प्राईम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जीन्द आये थे तो उन्होंने भी कहा था कि इसे जल्दी लगाने जा रहे हैं इस पर 1500 करोड़ रूपया खर्च होगा। यह कारखाना जल्दी ही लगेगा ओर इसकी मंजूरी हो गई है।

श्री कंवल सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके मंत्री द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस कारखाने के लगान के बाद कितने एनसिलरी यूनिटस लगने की सम्भावना है?

श्री श्रीकिान दास: एनासिलरी यूनिटस तो लगेगे लेकिन डिटेल में नहीं बताया जा सकता कि कितने लगेगें।

चौधरी लाल सिंह: स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेगे कि इसमें जो आदमी रखे जायेगे, वे एक ही हल्के के रखे जायेगे या दूसरे हल्कों के भी रखे जायेगें?

श्री श्रीकिान दास: यह कहना तो मुश्किल है कि किस हल्के के कितने रखे जायेगें। जिस हल्के के अच्छे काम करने वाले आयेगे उन्हें ही रखा जायेगा?

बहिन भान्ति देवी: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने बताया कि इस कारखाने में रोजगार देने के मामले में सरकार हरियाणा के लोगो को ख्याल रखेगी। यह कारखानो करनाल जिले में लग रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी, क्या प्रोपर करनाल के लोगो को रोजगार देने में प्रैफरैन्स देगे?

श्री श्रीकिान दास: यह तो कुदरती बात है कि जिस जगह पर फ़ैक्तर लगती है उस जगह के लोग फायदा उठाते हैं और दूसरे उस एरिया के लोगों का ज्यादा ख्याल भी रखा जायेगा।

Setting Up of Oil Refinery in the State

***1252 Sh. Bhale Ram & Sh. Nihal Singh:** Will the Minister for Irrigation and power be pleased to state the present stage of work for the construction of Dadupur-Nalvi Canal?

Irrigation & Power Minister (Ch. Shamsheer Singh Surjewala): The honorable Member is perhaps referring to the Shahabad Nalvi Scheme. The Scheme stands approved by the Government at a cost of about Rs. 21.90 crores. Land acquisition for the Shahabd Feeder is in progress. The alignment of the of the Feeder has been approved. The execution of the scheme will commence after the land has been acquired.

चौधरी साहब सिंह सैनी: अध्यक्ष महोदय, इस नहर के लिए 21.90 करोड़ रुपया रखा गया है। क्या जमीन एकवायर करने का प्रोसेस शुरू हो गया है, अगर हो गया है तो दफा चार और छः के नोटिफिके इन कितनी जमीन के हो गये हैं और अगर नहीं हुए है तो कितनी के नहीं हुए और ये नोटिफिके इन बक तक इ पू कर दिये जायेगे? यह चूकि बड़ी अहम नहर है इसलिए क्या

मन्त्री महोदय बताने को कष्ट करेगे कि अब तक उसके बारे में कितनी प्रोग्रेस हुई है?

चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला: इस नहर के लिए लैन्ड ऐक्वीजि ान का जो काम हुआ है उसकी डिटेल् इस प्रकार है:—

“The land Notification U/S 4 of Land Acquisition Act, 1894 from KM 5.397 to 18.922 has been published after getting the approval of land papers. Land documents U/S 6 from KM 5.397 to KM 11.454 also stand approved from Government. The land papers U/S 4 from KM 18.922 to 25.100 are unde process.”

So, Sir, these are diffenrent statges of land qcquisition.

सेठ राम दास धमीजा: स्पीकर साहब, मैम्बर साहब ने सवाल दादूपुर नलवी स्कीम के बारे में पूछा था जब कि जवाब में भाहबाद नलवी स्कीम दिया हुआ है। क्या मन्त्री महोदय बतायेगे कि किस नाम से यह स्कीम है, और क्या अम्बाला कैंट का भी इस स्कीम के तहत पानी मिलेगा?

चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला: मैम्बर साहब, ने ठीक फरमाया है। इस प्रोजैक्ट का पापुलर नाम दादूपुर नलवी कैंनाल है लेनि असली नाम भाहबाद नलवी स्कीम हैं। जहा तक अम्बाला कैंट का पानी देने का सवाल है इस वक्त अर्बन एरियाज का पानी देने का कोई प्रोवीजन नहीं है लकिन जब कोई नहर निकलती है

तो उससे अर्बन एरियाज को अगर पानी नहीं है लेकिन जब कोई नहर निकलती है तो उससे अर्बन एरियाज को अगर पानी मिल सकता है तो दे दिया जात हैं। इस नहर की डिटेल्स यह कैनाल अम्बाला और कुरुक्षेत्र के एरियाज का पानी देगी। इस नहर की डिटेल्स मैं हाउस को बता देता हूँ। टोटल लैन्थ आफ चैलन्ज 381.40 किलोमीटर होगी। इस नहर से 347 गांव अम्बाला और कुरुक्षेत्र जिले के इरिगेट होंगे जिनकी टोटल जमीन 75350 हैक्टेयर होगी और 21.90 करोड़ रुपया इस पर खर्च होगा। अगर आप बाउन्डरी भी पूछना चाहते हैं तो वह भी बता देता हूँ। The area under this Scheme is bound by Ladwa Pipli Road, SYL Canal, Tangri Nadi, Ambala-Jagadhri Railway Line and WJC Canal from Jagadhri to Dhanaura Escape, यह इसकी बाउन्डरी है। इस एरिया के अन्दर 347 गांव हैं जिनकी जमीनों को फायदा होगा। हल्के इसमें दर्ज नहीं है फिर भी ब्रोडली बता देता हूँ। जगाधरी, यमुनानगर के साथ के कुछ गांव, रादौर का एरिया, भाहबाद, मुलाना और नग्गल का एरिया आदि इससे बैनिफिटिड होंगे। इस प्रकार से इसमें 5-6 कांस्ट्रिचुऐसीस के गांव शामिल हैं।

चौधरी साहब सिंह सैनी: स्पीकर साहब, दादूपुर नलवी नहर के बारे में तो मंत्री महोदय ने डिटेल्स में बता दिया लेकिन जो नहर लाडवा के नाम से घनौरा ऐस्कैप से निकाली जाएगी, वह किस एरिया का पानी देगी? दादूपुर नलवी जो नहर है वह लाडवा पीपली रोड यानी सहारनपुर रोड तक नार्थ की ओर सिंचाई करेगी लेकिन दक्षिण की ओर काफी क्षेत्र—सहारनपुर,

कुरुक्षेत्र और सिरसा नहर के बीच आ जाता है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस बीच के एरिया की किस नहर से सिंचाई की जाएगी?

चौधरी भामदेव सिंह सुरजेवाला: एक दूसरी कैनल की प्रोजेक्ट है। हथीन कुण्ड एक नया बैराज बनेगा। यह स्कीम अन्डर प्रोग्रेस में है जो रिवालिफ फुटहिल्ज के साथ साथ कालका कांस्ट्रिक्ट्यूएसी और पंचकूला के एरिया से निकलेगी। मैम्बर साहब ने जो फरमाया है, यह दूसरी कैनल है। इस समय इसकी डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं। आप मेरे ऑफिस में आ जायें मैं इसका नक्शा आदि आपको दिखा दूंगा। जो भी मैम्बर इन्ट्रस्टिड हो ओर डिटेल्स पता करा चाहते हों वे किस एरिया को शामिल किया गया है और किस को शामिल नहीं करना चाहिए, वे आएँ और हमें बता दें।

श्री कंवल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने ताजेवाला बैराज को जिक्र किया है। मैं इनसे यह जानना चाहता हूँ कि जो यू.पी. के साथ हमारा कुछ डिस्प्यूट था, क्या वहाँ सौर्ट हो गया है, अगर हो गया है तो कब तक इस पर काम शुरू करने वाले हैं?

चौधरी भामदेव सिंह सुरजेवाला: ऐज सच हमारा यू.पी. से कोई डिस्प्यूट नहीं है। सारे पैरामीटर्स तकरीबन तकरीबन पूरे हो चुके हैं। लास्ट मिन्ट में कोई मामूली हिच आ जाये तो कह नहीं सकते। अभी पिछले दिनों हमारे मुख्यमंत्री जी ने यू.पी. के मुख्यमंत्री जी से बात की है। मैंने भी उनसे बात की है। इस

मामले में और फरीदाबाद कैनल सिस्टम को ट्रांसफर करवाने के मामले में होने उनसे यह रिक्वैस्ट की है कि जल्दी ही मीटिंग फिक्स करवा दे और वे इस काम के लिये ऐग्री भी कर गये हैं। पिछले दिनों जब वे कर्नाल में ब्रिज का फाउंडेशन स्टोन ले करने के सिलसिले में आये थे तो उस दिन वे इस बात के लिए ऐग्री कर गये थे कि वे दिल्ली में या कहीं और इस बारे में मीटिंग करके मामला सॉर्ट आउट कर लेंगे हमें उम्मीद है कि सरकार इस मामला को जल्दी ही सॉर्ट आउट कर लेगी।

चौधरी लाल सिंह: स्पीकर साहब, सिंचाई मंत्री जी ने मुलाना और कालका का जिक्र किया है लेकिन बीच में नारायणगढ़ जो फसा हुआ है उसका जिक्र करना भायद वे भूल गये हैं। (हंसी) नारायणगढ़ का जिक्र उन्होंने नहीं किया है। जनाबेआला, क्या वहां पर खेतों को पानी नहीं मिलेगा; लोग तो पानी के लिये तरस रहे हैं?

चौधरी भामदेव सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, हथिनी कुंड से जो दूसरी कैनल का तजवीज है, वह मेनली नारायणगढ़ के लिये ही है। इन्होंने बात सुनी नहीं है।

Construction of Level Crossing in Jind.

***1269 Sh. Brij Mohan:** Will the Minister for Public Works (B&R) be pleased to state—

(a) whether any funds for the construction of level crossing on the Bye-Pass on Bhiwani-Rohtak Road, in Jind

City have been placed at the disposal of Railway authorities by the Public Woks (B&R) Department;

(b) if so, whether the work for the construction of the said level crossing has been started; and

(c) if the reply to part (a) above be in the affirmative and to part (b) above be in the negative the reasons on account of which the work for the construction of said level crossing has not so far been the construction of said level crossing has not so far been undertaken together with the steps, if any, taken or proposed to be taken for getting the said construction works expedited?

Public Works Minister (Sh. Phool Chand):

(a) Yes; Rs. 2 Lacs.

(b) No.

(c) The matter regarding the sharing of cost has remained under correspondence with the Railway Deptt. The works could not be taken up till now as the State Government was not in a position to give an undertaking as required by the Railways that the total cost of a road over Bridge if and when required for replacing the proposed level crossing would be borne entirely by the Sate Government. Now the Railways have again been requested to provide the level crossing fro which cost has been deposited by the Sate Government Leaving the question regarding the Road Over Bridge to be settled at a future date.

श्री भले राम: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि सारे हरियाणा में रेलवे क्रॉसिंग्स कितने हैं किन किन पर यह पुल बने हुए हैं किन की मंजूरी मिल चुकी है और कौन से क्रॉसिंग्स पर काम भुरु है? (व्यवधान व भाोर)

श्री फूल चन्द: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के सारे भाहरो में बहुत सारे क्रॉसिंग्स हैं। कई जगहों पर ओवर ब्रिज बने हुए हैं ओर कुरुक्षेत्र, करनाल, रोहतक और भिवानी में काम प्रोग्रैस में है। जो क्रॉसिंग्स की बात इन्होंने कही है, भारत सरकार से 65 क्रॉसिंग्स बनाने के बारे में बात चल रही है।

चौधरी कुन्दन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो जींद में रोहतक रोड पर क्रॉसिंग है उसके बनाने के बारे में रेलवे विभाग से कोई बातचीत की गई है; यदि की गई है तो वह क्या है?

श्री फूल चन्द: अध्यक्ष महोदय, यह जींद का ही सवाल है। अब मैम्बर साहब रोहतक रोड क्रॉसिंग के बारे में जानना चाहते हैं या बाई पास के बारे में जानना चाहते हैं यह बात ये कृपया बताए?

चौधरी कुन्दन लाल: बाई—पास के बारे में।

श्री फूल चन्द: बाई पास की बात चल रही है।

श्री निहाल सिंह: स्पीकर साहब, रेलवे क्रॉसिंग की प्रोब्लम कई बार गांवो मे भी आती है। ऐसे कई रेलवे क्रॉसिंग है जहां गांव एक तरफ है और अस्पताल तथा दूसरी संस्थाए आदि दूसरी तरफ हैं। ऐसे रेलवे क्रॉसिंग भाम को 6 बजे के बाद बन्द करी देते है और 6 बजे के बाद चाहे कोई मरीज की क्यो न हो, वह कहीं आ जा नही सकता। क्या इस बारे मे मंत्री जी गवर्नमेंट आफ इंडिया से या रेलवे मिनिस्टरीसे मामला टैक-अप करेगें कि वहां पर सिंगल मैन क्रॉसिंग की बजाये डबल मैन क्रॉसिंग बना दिया जाये ताकि गांव वालों को सहूलियत हो सकें?

श्री फूल चन्द: अध्यक्ष महोदय जहां पर सडक बनी हुई है और साथ ही वहां पर अगर क्रॉसिंग है तो भारत सरकार के रेलवे विभाग का उस पर कंट्रोल है फिर भी जैसे कि आदरणीय सदस्य ने कहा है कि दिक्कत है हम उनकी दिक्कत को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को इस विशय में चिटठी लिखेंगे।

Issue of Gun/Revolver/Pistol licences

***1274. Chaudhri Azmat Khan:** Will the minister for Home be pleased to state the names and addresses of persons issued gun/revolver/pistol licences in Nuh, Ferozcpur Jhirkha and Palwal Sub-Divisions during the year 1986-87 (upto 31 st January, 1987) separately?

Home Minister (Chaudhri Tayyab Hussain): The requisite information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) List of persons to whom Arms Licences were issued during the year 1986-87 (1-4-86 to 31-1-87) in Nuh Sub-Division

1	2	3	4
1	104/Nuh/April/86	Om Parkash s/o Fateh Chand r/o Tauru	NPB Revolve
2	105/Nuh/April/86	Om Parkash s/o Chandgi Ram r/o Jorasi	DO
3	65/Nuh/June/86	Lal Khan s/o Jom Khan r/o Sunari	Gun
4	101/Nuh/July/86	Manager, SBI, Rojka Meo	Gun
5	102/Nuh/July/86	Harish Kumar s/o Lal Chand r/o Nuh	Rifle
6	103/Nuh/July/86	Nanak Chand s/o Ram Chand r/o Nuh	Gun
7	104/Nuh/July/86	Ali Mohd. s/o Subhan Khan r/o Adwar	Gun
8	105/Nuh/July/86	Habib Khan s/o Kole Khan r/o Sudaka	Gun
9	55/Nuh/Oct./86	Ala Bax Khan s/o Ramanjan Khan r/o Malai now constable PS Nuh	Gun

10	56/Nuh/Dec./86	Noor Mohd. s/o Jai Khan r/o Sunari	Gun
11	106/Nuh/Dec./86	Jawahar Singh s/o Faquira r/o Chhapera	Revolver
12	107/Nuh/Dec./86	Dalip Singh s/o Singh Ram SHO Tauru	Gun
13	94/Nuh/Jan./87	Jamil Ahmed s/o Rehmat r/o Kalika	Gun
14	95/Nuh/Jan./87	Noor Khan s/o Rehmat r/o Chilawali	Gun
15	96/Nuh/Jan./87	Om Parkash s/o Krishan Lal r/o Nuh	Gun

(b) List of persons to whom Arms Licences were issued during the year 1986-87 (1-4-86 to 31-1-87) in Ferozpur Jhirka Sub-Division

1	2	3	4
1	49/SDM (F)	Noor Mohd. s/o Kantula r/o Molhaka	DBBL Gun
2	50/SM (F)	Najir Ahmed s/o Jagdev r/o Badarpur	SBBL Gun
3	51/SDM (F)	Abdul Hakimas s/o Ghosi r/o Bisru	DMML Gun

4	60/SDM (F)	Dina s/o Nabi Bux r/o Mandhi	DBBL Gun
5	61/SDM (F)	Sahab Khan s/o Chattar Khan r/o Jadoli	SBBL Gun
6	62/SDM (F)	Fateh Mohd. s/o Rehmat r/o Mohd. Nagar	DBBL Gun
7	63/SDM (F)	Rustam s/o Dalla Khan r/o Moolthan	SBBL Gun
8	64/SDM (F)	Sardar Mohd. s/o Chand Khan r/o Tundlaka	SBBL Gun
9	33/SDM (F)	Yakub s/o Barat r/o Amka	DBBL Gun
10	36/SDM (F)	Sumer Khan s/o Nabi Khan r/o Tundlaka	SBBL Gun
11	37/SDM (F)	Abdul Salam s/o Umrao r/o Mohd. Nagar	DBBL Gun
12	38/SDM (F)	Abdul Majid s/o Fateh Khan r/o Badas	SBBL Gun
13	39/SDM (F)	Nanak Chand s/o Kala Khan r/o Badas	DBBL Gun
14	60/SDM (F)	Mohan Singh s/o Kalu Ram Reader DSP F.P. Jhirka	DBBL Gun
15	61/SDM (F)	Sarup Singh s/o Kanwal Singh Reader DSP F.P.	DBBL

		Jhirka	Gun
16	62/SDM (F)	Paraduman Singh s/o R.D. Chaudhry DSP F.P. Jhirka	Revolver
17	63/SDM (F)	Satish Chand s/o Chet Ram c/o DSP F.P. Jhirka	DO
18	64/SDM (F)	Sukhpal Singh s/o Dal Singh Const. P.S. Nagina	DO
19	65/SDM (F)	Brahm Parkash s/o Dal Chand Const P.S. Nagina	SBBL Gun
20	66/SDM (F)	Jagmender Singh s/o Chattar Constable P.S. Nagina	DBBL Gun
21	67/SDM (F)	Rakesh Yadav s/o O.P. Yadav c/o SDO F.P. Jhirka	DBBL Gun
22	68/SDM (F)	Ajay Kumar s/o Hari Chand r/o Nigan	Revolver
23	69/SDM (F)	Ass Mohd. s/o Budha r/o Molhaka	SBBL Gun
24	70/SDM (F)	Manphool Singh s/o Badal HMC PS F.P. Jhirka	DBBL Gun
25	71/SDM (F)	Fajar Khan s/o Niwaj Khan r/o Rehpwas	SBBL Gun
26	72/SDM (F)	Sami Khan s/o Niwaj Khan	SBBL

		r/o Raniyala F.pur	Gun
27	73/SDM (F)	Ishaq s/o Iqrahim r/o Dhanna	DBBL Gun
28	74/SDM (F)	Kamru din s/o Safed Khan r/o Kolgaon	DBBL Gun
29	36/SDM (F)	DN Sachdev s/o Sawan Ram r/o F.P. Jhirka	Revolver
30	37/SDM (F)	Manmohan Singh s/o Kishan Singh r/o F.P. Jhirka	DO
31	38/SDM (F)	Charan Singh s/o Kanwar Singh F.P. Jhirka	Revolver
32	39/SDM (F)	Ashwani Kumar s/o DN Sachdev r/o F.P. Jhirka	Revolver
33	40/SDM (F)	Yug Raj Singh s/o DS Sagar r/o F.P. Jhirka	Revolver
34	41/SDM (F)	Ali Mohd s/o Nasib Khan PS F.P. Jhirka	DBBL Gun
35	42/SDM (F)	Shamesh Khan s/o Nahangira r/o Ranika	SBBL Gun
36	43/SDM (F)	Kamrudin s/o Jahangira r/o Ranika	SBBL Gun
37	44/SDM (F)	Din Mohd. s/o Dilawar	SBBL

		Khan r/o Mohali	Gun
38	45/SDM (F)	Surender Kumar s/o Gulab Chand r/o F.P. Jhirka	Revolver
39	46/SDM (F)	Kanwar Khan s/o Mojit r/o Umri	SBBL Gun
40	47/SDM (F)	Bashir Ahmad s/o Umrao Khan r/o Nagina	SBBL Gun
41	43/SDM (F)	Kamru din s/o Sultan Khan r/o Amka	DBBL Gun
42	44/SDM (F)	Mohd. Ilyas s/o Hasan Khan r/o Badli	DBBL Gun
43	45/SDM (F)	Khurshid Ahmed s/o Mojal r/o Hukuka	SBBL Gun
44	46/SDM (F)	Din Mohd. s/o Nur Bux r/o Khan Mohdpur	SBBL Gun
45	47/SDM (F)	Aslup s/o Ishak r/o Bhadoli Kalan	SBBL Gun
46	48/SDM (F)	Mahinder Kishore s/o Siri Ram r/o F.P. Jhirka	Revolver
47	21/SDM (F)	Matin Khan s/o Abdul Rahman r/o Mandikhera	DBBL Gun
48	22/SDM (F)	Islam Khan s/o Gordhan r/o Ali Tighra	SBBL Gun

49	23/SDM (F)	Ruddar s/o Kherati r/o Mohkala	SBBL Gun
50	24/SDM (F)	Abdul Rahim s/o Paltu r/o Padla	SBBL Gun
51	40/SDM (F)	Ami Chand s/o Parbhati Lal r/o Patan	DBBL Gun
52	41/SDM (F)	Sirujudin s/o Juhar Khan r/o F.P Jhirka	SBBL Gun
53	42/SDM (F)	Manohar Lal s/o Gordhan r/o Nakanpur	DBBL Gun
54	43/SDM (F)	Nasaru din s/o Rustam Khan r/o Biwan	SBBL Gun

(c) List of persons to whom Arms Licences were issued during the year 1986-87 (1-4-86 to 31-1-87) in Palwal Sub-Division

Sr. No.	Date	Licence No.	Weapon	Address
1	2	3	4	5
1	1-4-86	150/P/April	Revolver	Mohinder Kalra S/o Parma Nand Kalra r/o Palwal. Teh. Palwal
2	3-4-86	151/P/April	Gun	Man Singh S/o Ram Chndi R/o Tumasra

				Teh. Palwal
3	3-4-86	152/P/April	Gun	Jugale Kishore S/o Tota Ram R/o Hodal Teh. Palwal
4	3-4-86	153/P/April	Revolver	Chhidi Lal S/o Arjun Lal R/o Palwal Teh. Palwal
5	10-4-86	154/P/April	Gun	Sant Ram S/o Chet Ram R/o Ali Brahaman Teh. Palwal
6	15-4-86	155/P/April	Gun	Mang Singh R/o Yad Ram Singh R/o Kherli Teh. Palwal
7	15-4-86	156/P/April	Gun	Mohinder Singh S/o Kartar R/o Bagpur Kala Teh. Palwal
8	17-4-86	157/P/April	Revolver	Subhash Chand S/o Nihal Chand R/o New Colony Palwal Teh. Palwal
9	24-4-86	159/P/April	Revolver	Pehlad S/o Khalyi Ram R/o Lalpur Kadim Teh. Palwal

10	24-4-86	160/P/April	Gun	Kamru S/o Chand Khan R/o Sapanki Teh. Hathin
11	30-4-86	161/P/April	Revolver	Nahar Singh S/o Ghar Singh R/o Rasulpur Teh. Palwal
12	5-5-86	089/P/May	Gun	Vijay Pal S/o Deep Chand R/o Dhatir Teh. Palwal
13	5-5-86	90/P/May	Gun	Gobind Singh S/o Chandi Ram R/o Chaprola Teh. Palwal
14	5-5-86	91/P/May	Revolver	Ranbir Singh S/o Ghasita Singh R/o Janoli Teh. Palwal
15	6-5-86	92/P/May	Gun	Sumer Singh S/o Med Singh R/o Kithwari Teh. Palwal
16	14-5-86	93/P/May	Gun	Tej Ram S/o Kishan R/o Alibrahmin Teh. Hathin
17	14-5-86	94/P/May	Gun	Rajinder Singh S/o Dallo Singh R/o

				Banchar Teh. Palwal
18	16-5-86	95/P/May	Gun	Fetha Singh S/o Bani Ram R/o Orangabad Teh. Palwal
19	22-5-86	96/P/May	Gun	Rati Ram S/o Mangli R/o Janoli Teh. Palwal
20	19-6-86	75/P/May	Revolver	Anil Goel S/o Tejpal Goel R/o Guptaganj Palwal Tehsil
21	19-6-86	76/P/May	Gun	Beer Singh S/o Kundan Singh R/o Janoli Teh. Palwal
22	26-6-86	77/P/May	Gun	Shir Chand S/o Tula Ram R/o Hansapur Teh. Palwal
23	26-6-86	78/P/May	Gun	Sudan Singh S/o Samya Singh R/o Hansapur Teh. Palwal
24	2-7-86	82-P/July	Revolver	Narender Kumar Mahajan S/o Durga

				Dass, Moh. Thai Teh. Palwal
25	3-7-86	23-P/July	Revolver	Anil Kumar S/o Tirloak Chand Kishanganj Teh. Palwal
26	3-7-86	84-P/July	Gun	Gurdev Singh S/o Hari Singh Kishanganj Teh. Palwal
27	4-7-86	85-P/July	Gun	Israj Khan S/o Allahabash R/o Ajijabad Teh. Palwal
28	17-7-86	86-P/July	Gun	Nathi Ram S/o Behla R/o Alike Teh. Palwal
29	26-7-86	27-P/July	Revolver	Girdhari S/o Bhola Ram R/o Aggarwal Colony Palwal
30	26-7-86	28-P/July	Gun	Khaniya Lal S/o Sukhdev SHO City Palwal, Teh. Palwal
31	5-8-86	168-P/Aug.	Revolver	Nath Kumar s/o Udayavir H.N. 1924

				GT Road, Palwal
32	5-8-86	169-P/Aug.	Gun	Munir S/o Mahtu R/o Huohpuria, Teh. Palwal
33	14-8-86	170-P/Aug.	Gun	Dharambir S/o Piare Lal R/o Bhambrola Jogi Teh. Hathin
34	14-8-86	171-P/Aug.	Gun	Deep Chand S/o Ami Chand R/o Bhambroha Jogi Teh. Palwal
35	18-8-86	172-P/Aug.	Gun	Rattan Lal S/o Sadhu Ram R/o Galpur Teh. Palwal
36	18-8-86	173-P/Aug.	Gun	Inder Singh S/o Ram Chand R/o Maholi Teh. Palwal
37	18-8-86	174-P/Aug.	Revolver	Yash Pal S/o Nand Lal R/o Dhundsa Teh. Palwal
38	28-8-86	177-P/Aug.	Gun	Jagdish Chand S/o Chiranji Lal R/o Taraka Teh. Palwal
39	2-9-86	179-P/Aug.	Revolver	Haran Singh S/o

				Amrit Lal New Colony Teh. Palwal
40	5-9-86	66-P/Sep.	Revolver	T.C. Tawatia S/o Kundan Singh R/o Janoli Teh. Palwal
41	5-9-86	67-P/Sep.	Gun	Om Parkash S/o Matadin R/o Thana Sadar Teh. Palwal
42	5-9-86	68-P/Sep.	Gun	Shiv Hari S/o Lal Singh R/o Pengaltu Teh. Palwal
43	5-9-86	69-P/Sep.	Gun	Sikander S/o Radhey Lal R/o Manpur Teh. Palwal
44	9-9-86	70-P/Sep.	Revolver	Subhash Chand S/o Chandi Lal Teh. Palwal
45	11-9-86	71-P/Sep.	Gun	Abdul Majid S/o Rehmat R/o Ali Meo Teh. Hathin
46	11-9-86	72-P/Sep.	Revolver	Subhash Choudhary S/o Kundan Singh R/o Palwal Teh. Palwal
47	16-9-86	74-P/Sep.	Gun	Bhagwan Singh S/o

				Khayali Ram R/o Lal Pur Kadim Teh. Palwal
48	19-9-86	75-P/Sep.	Gun	Virender Singh S/o Bali Ram R/o Lalwa Teh. Palwal
49	19-9-86	75-P/Sep.	Gun	Manager Coop. Bank Pirthla
50	23-9-86	77-P/Sep.	Revolver	Om ParkashS/o Chock Ram GT Road Teh. Palwal
51	1-10-86	99-P/Oct.	Gun	Arjun Singh S/o Attar Singh R/o Gelpur Teh. Palwal
52	1-10-86	100-P/Oct.	Rifle	Girraj Singh S/o Fehta Ram R/o Bahin Teh. Palwal
53	14-10-86	101-P/Oct.	Revolver	Dharam Pal S/o Rattan Singh R/oKalwaka Teh. Palwal
54	15-10-86	102-P/Oct.	Revolver	Smt. Sudesh Bhatia W/o KL Bhatia, New Colony, Palwal
55	15-10-86	103-P/Oct.	Revolver	Rajinder Parshad

				S/o Bhoram Lal R/o Pirthla Teh. Palwal
56	20-10-86	104-P/Oct.	Revolver	RP Gupta S/o MP Gupta R/o New Colony, Palwal
57	21-10-86	105-P/Oct.	Gun	Charan Singh S/o Ram Sarup R/o Budhiki Teh. Palwal
58	21-10-86	106-P/Oct.	Revolver	Rattan Lal S/o Sohan Lal R/o New Colony, Palwal
59	21-10-86	107-P/Oct.	Gun	Manager Commercial Bank Hassanpur Teh. Palwal
60	4-11-86	63-P/Nov.	Gun	Samrath Singh S/o Pachaman Singh R/o Aurangabad Teh. Palwal
61	7-11-86	64-P/Nov.	Gun	Nathi Singh S/o Deepa R/o Nagla Hathin
62	6-11-86	65-P/Nov.	Gun	Manager State Bank of Patiala

				Hathin
63	10-11-86	66-P/Nov.	Revolver	Achander Parkash S/o Pachman Dass, New Colony Palwal
64	17-11-86	67-P/Nov.	Revolver	Budhi Singh S/o Gyasi Ram R/o Janoli Teh. Palwal
65	11-11-86	68-P/Nov.	Revolver	Nand Kishore S/o Ram Kishan R/o Hodal
66	13-11-86	70-P/Nov.	Gun	Tara Chand S/o Heera Lal R/o Charrot Teh. Palwal
67	14-11-86	71-P/Nov.	Gun	Harpal Singh S/o Krishan Singh Inder pur Palwal, Teh. Palwal
68	14-11-86	72-P/Nov.	Revolver	Ajit Singh S/o Lal Chand ADA Palwal Teh. Palwal
69	14-11-86	73-P/Nov.	Gun	Shyam Singh S/o Gyasi Ram R/o Kakrali Teh. Palwal
70	18-12-86	117-P/Dec.	Gun	Nabab Khan S/o Shah Buddin R/o

				Hathin
71	29-12-86	118-P/Dec.	Gun	Manager PNB, Hodal Teh. Hodal
72	1-1-87	106-P/Jan.	Revolver	Ishwar Dutt S/o Gulab Singh R/o Pengaltu Teh. Palwal
73	1-1-87	117-P/Jan.	Gun	Narbir Singh S/o Pirtamber R/o Bhulwana Teh. Palwal
74	5-1-87	108-P/Jan.	Revolver	Om Parkash Tewatia S/o Devi Ram R/o Meerapur Teh. Palwal
75	5-1-87	109-P/Jan.	Gun	Bhagat Singh S/o Shyam Lal R/o Chanduat Teh. Palwal
76	5-1-87	110-P/Jan.	Gun	Bed Parkash S/o Pat Ram R/o Alike Teh. Palwal
77	8-1-87	111-P/Jan.	Gun	Tara Chand S/o Bhajan Lal R/o Gharrot Teh.

				Hathin
78	12-1-87	112-P/Jan.	Gun	Bal Kishan S/o Singh Ram R/o Andhop Teh. Hathin
79	12-1-87	113-P/Jan.	Gun	Kamrudin S/o Khudha Baks R/o Ajijabad Teh. Palwal
80	12-1-87	114-P/Jan.	Gun	Puran Singh S/o Roopi R/o Banswa Teh. Palwal
81	15-1-87	115-P/Jan.	Revolver	Man Mohan Singh S/o Gur Charan Jawhar Nagar Palwal, Teh. Palwal
82	15-1-87	116-P/Jan.	Revolver	Madan Lal S/o Jeewan Lal R/o 286, New Colony Palwal Teh. Palwal

चौधरी अजमत खां: स्पीकर साहब, जो इन्फर्मे इन हाउस की टेबल पर रखी गयी है। उससे जाहिर होता है कि नूह सब डिविजन में 15ए फिरोजपुर झिरका में 54 और पलवल सब डिविजन में 82 आदमियों को इस साल के दौरान लाइसेंस दिये गये हैं। आप देखें नूह में सबसे कम लाइसेंस दिये गये है। कहां

15 कहां 54 और कहा 82। नूंह के 15 आदमियों में से भी मेरे हल्के के सिर्फ 3-4 आदमियों को ही लाइसेंस मिले हैं। इसी तरह फिरोजपुर झिरका में 54 में से मेरे हल्के के केवल 11 आदमियों को और पलवल में हथीन तहसील के सिर्फ 8 आदमियों को ही लाइसेंस दिये गये है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि ऐसा करना हमारे साथ ज्यादाती नहीं है?

चौधरी तैयब हुसैन: स्पीकर साहब, इस सवाल का जवाब पिछले सै ान में आदरणीय मुख्यमंत्री जी दे चुके है। अगर मैं उन्हीं के भाब्दों को दोहरा दूं तो कोई गलती नहीं होगी। जिस जिस जगह पर जरूरत होती है उस जगह की जरूरत को देखते हुए लोकल अथारिटीज लाइसेंस देती है। इसीलिये ये पावर्ज हमने लोकल अथारिटीज को दे रखी है।

चौधरी अजमत खां: स्पीकर साहब, मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या मेरे हल्के के गांवों के लोग लाइसेंस मांगते ही नहीं है या उन्हें दिए ही नहीं जाते है? मैं समझता हूं कि मेरे हल्के के लोग भी लाइसेंस मांगते हैं मैं खुद इसका भुगतभोगी हूं। मैंने अपने बेटे के लिये लाइसेंस मांगा था। मेरे दादा की बन्दूक मेरे पास है। मैं यह चाहता था कि मेरे बेटे के नाम वह ट्रांसफर हो जाये। हमें यह कहा जाता है कि हम लाइसेंस देते ही नहीं है। लेकिन यहां पर इतनी लम्बी लिस्ट दी गयी है। मेरे हल्के का कोई भी आदमी इस काम के लिये रि वत नहीं देगा चाहे उसको लाइसेंस मिले या न मिले।

चौधरी तैयब हुसैन: स्पीकर साहब, मैं यह नहीं समझता कि मोअजिज मैम्बर को इस तरह की कोई इन-सिनुए इन करनी चाहिये। ऐसी कोई कंसीड्रे इन नहीं है। भायद आनरेबल मैम्बर को यह इल्म नहीं है कि लाइसेंस देना या न देना यह क्वासीजुडीसियल आर्डर है और अपीलबल आर्डर है। अगर किसी को कोई रंजि है तो अपील में जा सकता है। क्या इन्होंने किसी केस में प्रैसकाइब्ड अथोरिटी के सामने कोई अपील की है? हाउस में कीचड उछालने के लिए ऐसा कहना ठीक बात नहीं है।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, आपको भी भायद पता होगा कि कुछ लोग सिंगापुर या दूसरे बाहर की कंट्रीज से रिवाल्वर वगैरा लेकर आते हैं। लेकिन अब सुना जाता है कि वे ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि उनको लाइसेंस की प्रौबलम आ जाती है। मैं इनसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या अब ऐसे करने से उनको बन्द कर दिया गा है या कोई और बात है?

श्री अध्यक्ष: यह तो सेंट्रल सरकार का काम है। इनके बस की बात नहीं है।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, क्या ऐसी कोई चिटठी इनको आयी है।

चौधरी तैयब हुसैन: सर, मेरे इल्म मे तो कोई बात नहीं है। मोहतरिम मैम्बर इस बारे में नोटिस दे दें पता करके बतला देंगे।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): सर, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट हरियाणा सरकार के हाथ में नहीं है। इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट की पालिसी गवर्नमेंट आफ इंडिया तय करती है। भाायद इस बारे में कोई चेंज हुई है लेकिन उसके लिये हरियाणा सरकार पिक्चर में नहीं आती।

Providing of sewerage connections

***1231. Seth Ram Dass Dhamija:** Will the Ministr of State for Local Government be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide sewerage connections in the big cities of the State and charge the cost thereof in easy instalments from the owners of the buildings as are provided such connections; and

(b) If so, the time by which the said proposal is likely to materialize?

Minister of State for Local Government (Shri Lachman Dass Arora):

(a) No, Sir.

(b) The question does not arise.

सेठ राम दास धमीजा: स्पीकर साहब, पंजाब में ऐसी प्रोवीजन है कि सरकार अपने खर्चे पर सिवरेज का कनेक्शन

लोगों को प्रोवाइड करती है और कंज्यूमर्ज से किस्तों में पैसा वसूल करती है। आम आदमी सिवरेज का खर्चा बर्दा त नहीं कर सकता। स्पीकर साहब, सरकार सिवरेज पर लाखों करोड़ों रूपया खर्च करती है और आगे लोग अगर कनैक्शन न लें तो वह रूपया बेकार जाता है क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी प्रपोजल है कि लोगों को सिवरेज का कनैक्शन सरकार प्रोवाइड करें और फिर उसके खर्च को आसान किस्तों में लोगों से ले ले?

श्री लछमन दास अरोडा: स्पीकर साहब, जहां तक विचार करने का सवाल है ऐसी बातों पर विचार किया जा सकता है लेकिन जैसा इन्होंने पंजाब के बारे में बताया है स्पीकर साहब, वहां ऐसी कोई बात नहीं है। स्टेट में एक दो कमेटीज हैं जिनकी फाइनेंशियल पोलीसी इन कुछ अच्छी है और वे यह काम कर सकती है। अगर एक दो जगह ऐसा करवा दिया जाए तो दूसरी जगहों पर भी यह डिमान्ड होगी। इसलिए फिलहाल यह बात विचाराधीन नहीं है।

**Construction of new building of the Primary Health Centre
at Hassangarh**

***1245. Chaudhri Inder Singh Nain:** Will the Ministr for Health and Ayurveda be pleased refer to reply to

starred question No.1121, answered on the floor of the House on 27.2.1986 and state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct new building for the Primary Health Centre at village Hassangarh (Hisar); and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to materialize together with the estimated cost thereof?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री गोवर्धन दास चौहान):

क. जी हां।

ख. भवन का पूर्ण होना जमीन तथा धन की उपलब्धि पर निर्भर करेगा।

चौधरी इन्द्र सिंह नैन: मन्त्री महोदय ने पहले पार्ट का जवाब यस में दिया है और यह माना हे कि कंस्ट्रक्शन आफ बिल्डिंग फण्डज और जमीन की अवेलेबिलिटी पर डिपैन्ड करती है। स्पीकर साहब, जमीन पंचायत ने दे दी है और पैसा आज फाइनेंस मिनिस्टर दे देंगे। स्पीकर साहब, मैंने पार्ट बी में यह पूछा था कि कितना पैसा लगेगा? स्पीकर साहब, जब इन्होंने पैसा मांगा की नहीं है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसा कैसे दे देगा? क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस पीएचसी पर कितना पैसा लगेगा?

श्री गोवर्धन दास चौहान: स्पीकर साहब, पीएचसी की पूरी बिल्डिंग पर बारह लाख रूपया लगता है। इसकी कुछ

कंस्ट्रक्शन इन हुई है। यहां पर जमीन पंचायत से हैल्थ डिपार्टमेंट को ट्रांसफर नहीं हुई है। जब जमीन ट्रांसफर हो जाएगी तो जमीन के मुताबिक नक्शा बनाएंगे कि कितनी बिल्डिंग बनानी जरूरी है और उसके मुताबिक ऐस्टिमेंट बनाएंगे।

श्री कंवल सिंह: क्या मंत्री महोदय बताने की कोशिश करेंगे कि नई पीएचसी खोलने का क्या काइटेरिया है।

श्री गोवर्धन दास चौहान: स्पीकर साहब, जो भी पंचायत पीएचसी खुलवाना चाहे उसको चार एकड़ भूमि और पचास हजार रूपया जमा करवाना पड़ेगा।

श्री लाल सिंह: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पंचायत से जो जमीन ली जाएगी उसका पैसा पंचायत को दिया जायेगा।

श्री गोवर्धन दास चौहान: स्पीकर साहब, वह तो पंचायत की तरफ से डोनेशन आएगा। पंचायत को पैसा नहीं दिया जाएगा।

चौधरी इन्द्र सिंह नैन: क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि जमीन और पैसा मिलने के कितने दिन बाद ये पीएचसी की बिल्डिंग का काम शुरू करवा देंगे?

श्री गोवर्धन दास चौहान: स्पीकर साहब, जैसे ही हमें जमीन और पैसा उपलब्ध होगा हम जल्दी ही काम शुरू करवा देंगे।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, मेरे हलके में गगाना गांव है वहां पर भी अभी तक पीएचसी नहीं खोली हुई है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कितने गांवों की दरखास्तें पीएचसी खोलने के लिए आई हुई है और कितने केसिज इनके पास पेंडिंग पड़े हुए है और कितनी जगहों पर इन्होंने पीएचसी खोल दी है?

श्री गोवर्धन दास चौहान: स्पीकर साहब, यह इन्फर्मे 11 न मेरे पास नहीं है लेकिन जहां से पैसा और जमीन हमें मिल गई है वहां पर हमारी को 11। यही है कि जल्दी की प्रायोरिटी बेसिज पर वहां पर काम शुरू करवा दें।

चौधरी कुन्दन लाल: स्पीकर साहब, मेरे हलके में मुआना गांव है। वहां की पंचायत ने आठ किल्ले जमीन दो साल हुए इनके नाम कर दी है और चालीस हजार रूपया भी जमा करा दिया है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उस काम को जल्दी करवा दिया जाएगा?

श्री गोवर्धन दास चौहान: स्पीकर साहब, इस तरह की बात मेरे नोटिस में नहीं है। मैम्बर साहब मेरे पास आ जाएं तो मैं सारी बात इनको बता दूंगा।

श्री निहाल सिंह: स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने बताया है कि पीएचसी खोलने के लिए चार एकड जमीन देनी पडती है और पचास हजार रूपया जमा कराना पडता है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अगर हरेक गांव जमीन और पैसा दे दे तो हर जगह पीएचसी खोल दी जाएगी और एक पीएचसी और दूसरी पीएचसी में कितना अन्तर होना जरूरी है?

श्री गोवर्धन दास चौहान: स्पीकर साहब, तीस हजार की आबादी पर हम एक पीएचसी खोलते है।

मास्टर राम सिंह: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि मेरे हलके के खानपुर कोलियान और बबैन में पीएचसी खोलने का काम कब तक भुरु कर दिया जाएगा?

श्री गोवर्धन दास चौहान: स्पीकर साहब, यह क्वै चन हसनगढ के बारे में है। मैम्बर साहब जो पूछ रहे है वह इंफर्मे तान मेरे पास नहीं है। वे मेरे पास आ जाएं मैं उन्हें बता दूंगा।

Setting up of Sugar Mills in Haryana

***1257. Shri Bhalle Ram:** Will the Minister of state for cooperative be pleased to state the number of Sugar Mills, if any, proposed to be set up in the state during the Seventh Five Year Plan period together with the names of places where such Sugar Mills are likely to be set up?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री प्यारा सिंह): भूना, कैथल तथा गोहाना में प्रत्येक स्थान पर 1250 टीसीडी क्षमता की चीनी मिलें स्थापित करने का मामला राज्य सरकार/भारत सरकार के विचाराधीन था परन्तु 12-12-1986 को सातवीं योजना के अन्तर्गत नई चीनी मिलों के बारे में घोषित की गई नीति के अनुसार नए लाइसेंस 2500 टीसीडी की क्षमता के ही जारी किये जा सकते हैं। समितियों द्वारा आगत पत्र प्राप्त करने हेतु अब नये प्रार्थना पत्र दिये जाने हैं।

श्री भले राम: मंत्री महोदय ने जवाब में बताया है कि हरियाणा में भूना कैथल और गोहाना में प्रत्येक स्थान पर 1250 टीसीडी क्षमता की चीनी मिलें स्थापित करने का मामला भारत सरकार के विचाराधीन था लेकिन भारत सरकार ने नई चीनी मिलों के बारे में नई नीति बना ली और अब नए लाइसेंस 2500 टीसीडी की क्षमता के ही जारी किये जा सकते हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि राज्या सरकार उन्हीं ऐप्लीकेटों को नई कैपेसिटी के अनुसार रिकमैन्ड करेगी या नई ऐप्लीकेटों मांगी जाएगी और टीसीडी का मतलब क्या है?

श्री प्यारा सिंह: टी0 का मतलब है टन। सी0 का मतलब है कैपेसिटी और डी0 का मतलब है डेली। अब 2500 टीसीडी कैपेसिटी से कम के लिए लाइसेंस नहीं मिल सकता। इसलिए अब नई ऐप्लीकेटों लाइसेंस के लिए देनी पड़ेगी। नई नीति के अनुसार 2500 टीसीडी कैपेसिटी के लिए ही लाइसेंस इतने लिए

जाएंगे। भारत सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए केवल भूना और कैथल सहकारी मिलें ही उपरोक्त भातों को पूरी कर सकती है। गोहाना भारत सरकार की नई नीति को पूरा नहीं करता।

श्री भले राम: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अगर गोहाना नई नीति को पूरा नहीं करता तो क्या बाकी दोनों मिलें भातों को पूरा करती है?

श्री प्यारा सिंह: दोनों जगह भूना और कैथल सहकारी चीनी मिलें ही भातों को पूरा करती है।

श्री भले राम: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि एक मिल और दूसरी मिल में कितना अन्तर होना चाहिए?

श्री प्यारा सिंह: स्पीकर साहब, एक मिल और दूसरी मिल में चालीस किलोमीटर का फासला होना चाहिए।

श्री कंवल सिंह: स्पीकर साहब, नई भूगर मिलों की कैपेसिटी भारत सरकार ने बढ़ाई है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यदि ऐग्जिस्टिंग भूगर मिलों पर ज्यादा लोड हो गया तो उनकी कैपेसिटी बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी?

श्री प्यारा सिंह: जो नई मिलें चालू होगी उनकी कैपेसिटी तो भारत सरकार की नीति के अनुसार ही होगी, वैसे हमारा विचार भाहबाद की मिल की कैपेसिटी बढ़ाने का है।

चौधरी सूबे सिंह पूनिया: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जींद की भूगर मिल की कैपेसिटी बढ़ाने का कोई विचार है?

श्री प्यारा सिंह: स्पीकर साहब, जींद की भूगर मिल की कैपेसिटी 1250 टीसीडी है। अगर वहां पर ज्यादा गन्ना आएगा तो उसकी कैपेसिटी बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, मैं पिछले पांच सालों से गोहाना के अन्दर भूगर मिल के सम्बन्ध में लडाई लडता जा रहा हूँ। मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में बताया है कि वर्तमान यूनिट के 40 किलोमीटर के क्षेत्र में नई चीनी मिल स्थापित करने के बारे में लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। गोहाना से सोनीपत लगभग 36 किलोमीटर है। पानीपत का भी भायद इतना ही फासला है। जींद का फासला भी गोहाना से लगभग 40 किलोमीटर से ज्यादा ही होगा। इसलिये मिल लगाने के लिये यह डिसटैन्स का कायटेरिया जो सरकार ने रखा है उचित नहीं है। जहां पर गन्ने की उपज ज्यादा हो वहां नई भूगर मिल लगाने की व्यवस्था होनी चाहिये, जैसे गोहाना से 10 किलोमीटर के अन्दर अन्दर आपको काफी गन्ना उपलब्ध हो जाएगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार इस डिसटैन्स के कायटेरिया को बदल कर जहां गन्ना ज्यादा पैदा होता हो उस बात को मददेनजर रखते हुए नई भूगर यूनिटस लगाने का विचार करे।

श्री प्यारा सिंह: भारत सरकार की नयी नीति के अनुसार प्रस्तावित मिल के आसपास गन्ना काफी मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए वरना वर्तमान यूनिट के 40 किलोमीटर के क्षेत्र में नई चीनी मिल स्थापित करने के बारे में लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। अगर गोहाना 40 किलोमीटर के अन्दर अन्दर नहीं आता तो वहाँ पर मिल लगाने पर विचार करेंगे।

श्री कंवल सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो जींद एरिया में बौडिड भूगर केन है उसको आप कब तक कटा करवा दोगें? मेरे हल्के में एक सिसाए गांव है वहाँ के किसान लगातार कई बार एमडी साहब को और मुख्यमंत्री महोदय के इस बारे में मिल भी चुके हैं कि वहाँ का गन्ना उठाया नहीं जा रहा है क्या सरकार इसका कोई प्रबन्ध करेगी?

श्री प्यारा सिंह: स्पीकर साहब, इस साल जींद में 15 लाख टन और पानीपत में 16 लाख टन गन्ना पीडा गया। आशा है कि इस वर्ष यह क्षमता बढ़ कर 15 अप्रैल 1987 तक 20 लाख टन हो जाएगी। इस तरह से किसानों को किसी किसम की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।

चौधरी इन्द्र सिंह नैन: स्पीकर साहब मैं आपकी मार्फत मुख्यमंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि जो मिलें पहले ही चालू हैं उन सब में आज तक कितना लाभ और कितना हानि हुई है?

श्री प्यारा सिंह: स्पीकर साहब, पिछले साल पलवल भूगर मिल से 227 लाख रुपये का घाटा हुआ और इस साल यह घाटा एक करोड़ रह जायेगा। जींद में पिछले साल 155 लाख रुपये का घाटा और इस साल 13 लाख रुपये का नफा होने की सम्भावना है। पानीपत में पिछले साल 30 लाख का नफा हुआ और इस साल 25 लाख नफा होने की सम्भावना है। रोहतक में 1985-86 में 50 लाख नफा हुआ और इस साल 1986-87 में 60 लाख का फायदा होगा। करनाल में 1985-86 में साढ़े 73 लाख रुपये का नफा हुआ और इस साल 80 लाख नफा होने की सम्भावना है। सोनीपत में पिछले साल 10 लाख का नफा हुआ और 1986-87 में 40 लाख का नफा होने की आशा है। इसी तरह से भाहबाद में पिछले साल 149 लाख का घाटा हुआ और इस साल 60 लाख का नफा होने की आशा है।

मास्टर राम सिंह: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि जितना बॉन्डिड गन्ना है क्या वह सारे का सारा ले लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: यह सवाल तो नयी भूगर मिलज खोलने के बारे में है। जायज क्वै चन पूछो तो मिनिस्टर साहब उसका जवाब भी देंगे। सारी सूचना ऑफ हैण्ड इनके पास कैसे हो सकती है?

श्री नेकी राम: अध्यक्ष महोदय, इस समय हरियाणा के अन्दर तीन नयी मिलें खोलने का सवाल जेरेगौर है। मेरा हल्का घग्गर बैल्ट में पडता है जहां गन्ना, चावल और गेहू की उपज सब से ज्यादा होती है। जाखल टोहाना और सिरसा तक यह सारी बैल्ट एक ही है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस उपज को ध्यान में रखते हुए ये जो भूना में मिल लगाने का सरकार का विचार है क्या इस के सीन पर रतिया के इलाके में यह मिल नहीं लगायी जा सकती? क्या इस मिल को रतिया में फिट कर दिया जायेगा?

श्री प्यारा सिंह: स्पीकर साहब, भूना में 1250 टीसीडी गन्ना पीडने की लाइसेंस की दरखास्त दी हुई थी। इनके एरिया का गन्ना जो मिलें लगी है उनमें आ जाएगा। इनके एरिया वालों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।

तारांकित प्र न संख्या @1253

श्री अध्यक्ष: यह प्र न पंजाब टैरिटरी में एसवाईएल कैनल को प्रोग्रेस के बारे में है। इसे मैं कल के लिए डैफर करता हूं

Construction of new roads in the State

***1265. Chaudhri Roshan Lal Arya:** Will the Minister for Public Works (B&R) be pleased to state the constituency wise total number of new roads, if any, constructed or on which work has been started in the State during the period from 1st June, 1986 to 1st February, 1987?

लोक निर्माण मंत्री (श्री फूल चन्द): सूचना इकट्ठी करने में जो समय और परिश्रम लगेगा उससे सम्भावित लाभ की प्राप्ति नहीं होगी।

Mr. Speaker: Question are over.

वर्ष 1987-88 का बजट पे 1 करना

श्री अध्यक्ष: अब फाइनेंस मिनिस्टर साहब वर्ष 1987-88 के लिए बजट प्रेजेंट करेंगे।

वित्त मंत्री (चौधरी कटार सिंह छोकर): माननीय अध्यक्ष महोदय और मेरे माननीय साथियो।

इस गरिमामय सदन के सामने हरियाणा सरकार के वर्ष 1986-87 के बजट अनुमान प्रस्तुत करते हुए मैं अत्यन्त सम्मान एवं भाग्य अनुभव कर रहा हूँ।

15.00 बजे

हमारे प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में गत वर्ष 1986-87 भारत के आर्थिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण सीमाचिन्ह

रहा है। इस वर्ष के दौरान देश को 2000 इसवीं के लिये तैयार करने के लिए भारत सरकार ने एक नीति अपनाई है जिसमें भरसक टैक्नोलौजी प्रयत्न एवं आयात को उदार बनाने तथा निर्यात को आकर्षक प्रोत्साहन देने का सुन्दर मिश्रण है। केंद्रीय करों की वसूली से सम्बन्धित मीनिरी को कारगर बनाने से केंद्रीय आय में सराहनीय बढौतरी हुई है। इसके फलस्वरूप इनमें से कुछ साधनों में राज्य का भाग भी बढ गया है।

सामाजिक-आर्थिक विकास की गति तेज करने तथा इस क्षेत्र की अमान्त स्थितियों की असुविधा को दूर करने के लिये प्रधानमंत्री ने सतलुज-यमूना योजक नहर परियोजना के पूरे खर्च का जिम्मा लेने की केंद्रीय सरकार की सहमति की घोशणा की। इस पर राज्य सरकार को अन्यथा चालू वित्त वर्ष की समाप्ति तक 200 करोड रूपये खर्च करने पडते। इसके अलावा इस वर्ष प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले विभिन्न भागों में तत्काल राहत उपायों के लिये केंद्रीय सरकार ने 17.25 करोड रूपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सरकार ने विभिन्न सिचाई बिजली उत्पादन कृषि पशुपालन जल सप्लाई शिक्षा चिकित्सा शिक्षा खेल-कूद तथा पर्यटन स्कीमों को बढावा देने के लिए भी काफी अतिरिक्त सहायता की घोशणा की है। मैं इस बहुमूल्य केंद्रीय सहायता की हृदय से सराहना करता हूँ।

हरियाणा 1986-87 का आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज माननीय सदस्यों के पास पहले ही है परन्तु मैं इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा।

मौसम की अनिश्चितता के बावजूद 1985-86 के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सरसरी अनुमानों के अनुसार राज्य की आय में पिछले वर्ष में चालू कीमतों पर 4654 करोड़ रुपये से 1985-86 में 5379 करोड़ रुपये होकर 15.6 करोड़ रुपये से 1784 करोड़ रुपये होकर 12.6 प्रति शत की वृद्धि हुई। राज्य की आय में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1984-85 में चालू कीमतों के अनुसार 10.3 प्रति शत की तथा 1970-71 की कीमतों पर 5.4 प्रति शत की बढ़ोतरी हुई। इस प्रकार राज्य की अर्थव्यवस्था में राज्य आन्तरिक उत्पाद की बढ़ोतरी की दर में सराहनीय वृद्धि देखने में आई है।

पिछले वर्ष की तुलना में 1970-71 की कीमतों पर आधारित राज्य आन्तरिक उत्पाद के क्षेत्रीय वितरण में 1985-86 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में 13.2 प्रति शत द्वितीय क्षेत्र में 9.0 प्रति शत और तृतीय क्षेत्र में 14.0 प्रति शत की बढ़ती हुई। यह महत्वपूर्ण प्रगति के रूझान को दर्शाता है। वर्ष 1984-85 में पिछले वर्ष की तुलना में 1970-71 की कीमतों के अनुसार राज्य आन्तरिक उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र में 3.7 प्रति शत द्वितीय क्षेत्र में 8.0 प्रति शत और तृतीय क्षेत्र में 6.3 प्रति शत की वृद्धि हुई। वर्ष 1970-71 की कीमतों के अनुसार वर्ष 1984-85 में तृतीय वर्ष में

प्रगति 496.06 करोड रूपए से 1985-86 में 565.37 करोड रूपये हो गई जो कि राज्य की आर्थिक व्यवस्था में विविधता लाने का प्रमाण है।

चालू कीमतों के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1984-85 में 3259 रूपए 1985-86 में हो गई, जो बढ़ती 12.6 प्रति ात है। चालू कीमतों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय पिछले साल के मुकाबले में 1984-85 में 7.3 प्रति ात बढ़ गई थी और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर में प्रगति अर्थव्यवस्था की समृद्धि की सूचक है।

कीमतें

अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्त कीमत सूचकांक (आधार वर्ष 1960-100) में मार्च 1985 और मार्च 1986 के बीच 8.9 प्रति ात तथा दिसम्बर 1986 तक 7.8 प्रति ात की और बढ़ती हुई। इसकी तुलना में हरियाणा राज्य श्रमिक वर्ग उपभोक्ता कीमत सूचकांक (आधार वर्ष 1972-73-100) में मार्च 1985 से मार्च 1986 तक 8.5 प्रति ात की वृद्धि हुई और दिसम्बर 1986 तक 5.9 प्रति ात तक की और बढ़ातरी हुई। इस प्रकार राज्य सरकार आवश्यक वस्तुओं की मांग तथा पूर्ति के बीच सूक्ष्म सन्तुलन बनाए रखकर कीमतें काबू में रख सकी है। हमारे यहां उचित मूल्य की 6400 से अधिक दुकानों का जाल बिछा हुआ है जिनमें से 4600 से अधिक ग्रामीण क्षेत्र में है। ये उचित मूल्य की दुकानें

राज्य के लोगों को बढ़िया किस्म की दालें, चीनी, चाय, नमक, मिट्टी के तेल तथा कापियां जैसी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित कर रही है। इन उचित मूल्य की दुकानों का स्थान इस प्रकार नियत किया गया है कि श्रमिक बस्तियों के निवासियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को पूरा लाभ मिल सके।

पूंजी निर्माण

सरकार की बजट व्यवस्था, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में पूंजी निर्माण के लिए बचत करके तथा उसे पूंजी परिसम्पतियों में लगाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राज्य सरकार के वर्ष 1986-87 के बजट अनुमानों के आर्थिक प्रत्यक्ष मांग 184 करोड़ रूपए हो गई। इसके अतिरिक्त 174 करोड़ रूपये की एक और राशि निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रति राज्य के अंशदान के रूप में निर्धारित की गई। इस प्रकार चालू वित्त वर्ष के दौरान 358 करोड़ रूपए की कुल पूंजी के निर्माण का अनुमान है जो कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक है।

सातवीं पंच-वर्षीय योजना

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के लिए 2900 करोड़ रूपये के खर्च की व्यवस्था की गई है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक प्रगति तथा आय और धन का समतावादी वितरण, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता तथा श्रम की उत्पादकता में वृद्धि करना है। कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के लिए बिजली का

अधिक महत्व मानते हुए, इस क्षेत्र के लिए कुल योजना खर्च का 34.8 प्रति अत भाग रखा गया है। अर्थ-व्यवस्था के भूमि प्रधान स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, सिंचाई तथा बाढ़ की रोकथाम के लिए, योजना खर्च का 20.5 प्रति अत रखा गया है जबकि कृषि तथा उससे सम्बन्धित क्षेत्र के लिए 8.2 प्रति अत राशि खर्च होगी। मानव संसाधनों तथा विकास में घनिष्ठ सम्बन्ध मानते हुए, खर्च का 19.2 प्रति अत भाग सामाजिक सेवाओं के लिए रखा गया है जिसमें शिक्षा के लिए 4.75 प्रति अत राशि शामिल है। परिवहन क्षेत्र को कुल खर्च का 6.9 प्रति अत मिलेगा। योजना से राज्य आन्तरिक उत्पाद में 6 प्रति अत की दर से वार्षिक प्रगति होने की संभावना है।

वार्षिक योजना 1986-87

वर्ष 1986-87 की वार्षिक योजना के लिए 525 करोड़ रूपए खर्च रखा गया था। सामाजिक आर्थिक विकास की गति में तेजी लाने के लिए अब इस राशि को बढ़ाकर 569.62 करोड़ रूपये कर दिया गया है। वार्षिक योजना के अन्तर्गत सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण पर 182.47 करोड़ रूपये की राशि के खर्च किए जाने की संभावना है। इसमें 90 करोड़ रूपए सतलुज यमुना योजना नहर के लिए, 166.69 करोड़ रूपए बिजली उत्पादन के लिए, 14.72 करोड़ रूपए कृषि तथा उससे सम्बन्धित क्रियाकलापों के लिये, 14.27 करोड़ रूपए ग्रामीण विकास के लिए, 35.34 करोड़ रूपए परिवहन तथा संचार के लिए तथा 92.82 करोड़ रूपये

सामाजिक सेवाओं के लिए शामिल हैं। इस प्रकार सरकार अर्थ-व्यवस्था की संतुलित प्रगति करना चाहती है।

बीस सूत्री कार्यक्रम

राज्य सरकार बीस सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है। समाज के कमजारे वर्गों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए, 51075 नये परिवारों को अप्रैल 1986 से जनवरी 1987 क आय के सहायक साधन प्रदान किए गए हैं जिनमें अनुसूचित जातियों के 35523 परिवार शामिल हैं इसके अतिरिक्त 9064 पुराने परिवारों को सहायता की दूसरी कि त प्रदान की गई है जिसमें अनुसूचित जातियों के 3758 परिवार शामिल हैं। इसी अवधि के दौरान, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत 21.39 लाख श्रम दिनों का रोजगार पैदा किया गया है। 360 ग्रामों को पीने का पानी सप्लाई किया गया है और आ ता है कि 504 ग्रामों का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। 10,000 पंप सैटों को बिजली देने के नि ाने के मुकाबले में पहली जनवरी, 1987 तक ही 10,138 पंप सैटों को बिजली पहुंचा दी गई थी और अब नि ाना 25,000 तक बढ़ा दिया गया हैं। वर्ष के पहले दस महीनों के दौरान, 725 लाख वृक्षों के नि ाने के मुकाबले में 643.90 लाख वृक्ष लगाए गए हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम को लागू करने के लिए, 59308 नसबन्दी आप्रे ान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 2541 व्यक्तियों को मकानों के लिए

जगह दी गई है और प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक बनाने के कार्यक्रम के अधीन 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के 23.79 लाख बच्चों को दाखिल करने के प्रगति मिल लक्ष्य के मुकाबले में, दिसम्बर, 1986 तक 23.70 लाख बच्चे दाखिल किए गए हैं। इस प्रकार राज्य ने, बीस सूत्री कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।

वार्षिक योजना 1987-88

वर्ष 1987-88 की योजना के लिए, खर्च 585.75 करोड़ रूपए नियत किया गया है। बिजली उत्पादन तथा सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण को विशेष महत्व देते हुए 195.04 करोड़ रूपए तथा 162.75 करोड़ रूपए का खर्च प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त कृषि तथा उससे सम्बन्धित क्रियाकलापों के लिए 47.72 करोड़ रूपए, ग्रामीण विकास के लिए 13.36 करोड़ रूपए, परिवहन तथा संचार के लिए 30.86 करोड़ रूपए और समाज सेवाओं के लिए 113.23 करोड़ रूपए के खर्च का प्रस्ताव है।

सिंचाई

सिंचाई खेती बाड़ी की रीढ़ की हड्डी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, सतलुज-यमुना योजक नहर परियोजना को छोड़कर बड़ी तथा मंझली कृषि परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 49.44 करोड़ रूपए के खर्च का प्रस्ताव है। पानी के रिसाव की हानि को घटाकर जल-व्यवस्था में सुधार लाने के लिए, वि व

बैंक की सहायता से नहरों को आधुनिक बनाने पर 19.92 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे। ऐसा अनुमान है कि इस परियोजना के पूरा होने पर दो लाख हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई हो सकेगी। राज्य के बंजर तथा असमतल क्षेत्रों में उठान सिंचाई जुटाने हेतु इस समय जवाहर लाल नेहरू नहर तथा लोहारू उठान सिंचाई योजना के चल रहे कार्य के लिए 9.5 करोड़ रूपए की राशि रखने का प्रस्ताव है। इसमें अतिरिक्त बंजर क्षेत्रों में छिड़काव सेटो पर एक करोड़ रूपए की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार 1987-88 के दौरान 53000 हैक्टेयर से अधिक अतिरिक्त सिंचाई क्षमता पैदा करने का प्रस्ताव है।

बाढ़ नियन्त्रण

बाढ़-नियन्त्रण तथा सेम रोकने के उपायों के लिए 13 करोड़ रूपए रखे जा रहे हैं। मसानी में सहिबी बांध के निकट भविष्य में पूरे होने की संभावना है अगले वित्त वर्ष के दौरान खारा, छुड़ानी तथा बहादुरगढ़ नालों के पूरे किए जाने तथा रोहतक के निकट लाला संख्या 8 की क्षमता 1000 क्यूसेक से बढ़ाकर 1650 क्यूसेक करने का प्रस्ताव है। बाढ़ों की चपेट में आने वाले 18.5 लाख हैक्टेयर के कुल क्षेत्र में से 1987-88 के अन्त तक 16 लाख हैक्टेयर के बचाव की आशा है।

सतलुज यमुना योजक नहर परियोजना

रावी व्यास जल प्रणाली का अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए सतलुज यमुना योजक नहर हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नहर की कुल लम्बाई लगभग 200 किलोमीटर होगी जिसमें से हरियाणा में आने वाली 92 किलोमिटर पहले ही पूरी कर ली गई हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, केन्द्रीय सरकार इस परियोजना का सारा खर्च पूरा करना मान गई है। हमारे राज्य के लिए यह एक बहुत बड़ा लाभ है क्योंकि नहर के पंजाब के भाग को पूरा करने में देरी के कारण परियोजना का बढ़ रहा है खर्च हमारे साधनों पर गम्भीर बोझ डाल रहा था। सतलुज यमुना योजक नहर के लिए 1987-88 के दौरान 71.40 करोड़ रूपए राशि रखने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय सरकार से, नहर के निर्माण का कार्य अपने हाथ में लेने तथा इसे भीघ संपन्न कराने के लिये अनुरोध किया गया है।

बिजली

राज्य सरकार बिजली उत्पादन बढ़ाने और उसे पहुंचाने तथा बांटने की प्रणाली को सुधारने के लिये जोरदार प्रयत्न कर रही है। इस उद्देश्य हेतु वार्षिक योजना के लिए कुल खर्च का 34 प्रतिशत भाग बिजली क्षेत्र पर किए जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1986-87 के दौरान यमुनानगर पन-बिजली परियोजना के 8 मेगावाट वाले 2 यूनिट चालू किए गए हैं और दो यूनिट निकट वर्ष में चालू किए जाने हैं। इसके अतिरिक्त 8 मेगावाट वाले 2 और यूनिट वर्ष 1987-88 के दौरान लगाए जाने की भी संभावना

हैं। इसके साथ ही पानीपत प्लांट में 110 मेगावाट चौथा यूनिट का एक समय भी आरम्भ किया गया है और इसके वाणिज्यिक उत्पादन के भीघ्र ही प्रारम्भ होने की संभावना है। 210 मेगावाट के पांचवे यूनिट का बहुत सा कार्य 1987-88 के दौरान पूरा कर लिया जाएगा। यमुनानगर थर्मल बिजली परियोजना पर निर्माण कार्य भी भुरू किए जाने की संभावना है नलकूपों को बिजली पहुंचाने के क्षेत्र में आगामी वित्त वर्ष के लिये 20000 नलकूपों को बिजली प्रदान करने का बड़ा लक्ष्य रखने का प्रस्ताव है इस प्रकार राज्य सरकार, राज्य की अर्थ व्यवस्था के कृषि व्यवस्था के कृषि औद्योगिक वाणिज्यिक और घरेलू क्षेत्रों को बिजली जुटाने की व्यापक नीति का अनुसरण कर रही है।

कृषि

किसानों हरियाणा कृषि वि विद्यालय, हिसार तथा राज्य सरकार के निश्ठापूर्वक प्रयत्नों को ध्यान में रखते हुए, यह राज्य राष्ट्र के खाद्य भण्डार में लगभग 5.4 प्रति ात का योगदान करता है जबकि इसके पास दे ा के कुल कृषि अधीन क्षेत्र का केवल 1.94 प्रति ात भाग है। राज्य को पिछले वर्ष पतझड़ मौसम में अभूतपूर्व सूखे का सामना करना पड़ा। राज्य को पिछले वर्ष पतझड़ मौसम में अभूतपूर्व सूखे का सामना करना पड़ा। सीलन के अभाव के कारण अनाज की फसलों वि ोशकर बाजरे को भारी नुकसान पहुंचा। सूखा पीड़ित किसानों की सहायता के लिए राज्य सरकार ने राज्य भर में रबी बीज पर 25 प्रति ात की दर से

रियायत देने के लिये एक करोड़ रुपये पहले ही स्वीकृत कर दिये हैं। गेहूं संबन्धी घासपात ना एक दवाइयों की लागत में 50 प्रति टा की दर से रियायत देने के लिये 111.72 लाख रुपये की राशि रखी गई है। रासायनिक खादों को 25 प्रति टा की दर से सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने के लिए 2.50 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है, जिसमें से अत्यधिक सूखा ग्रस्त जिलों में अधिक सहायता 165 रूपए प्रति किसान होगी। वर्ष 1987-88 के दौरान अनाजों का 81.80 लाख टन का लक्ष्य से 5.3 प्रति टा अधिक है। वर्ष 1987-88 के दौरान अनाजों का 81.00 लाख टन का लक्ष्य निश्चित किए जाने का प्रस्ताव है जो पिछले वर्ष के लक्ष्य से 5.3 प्रति टा अधिक है। वर्ष 1987-88 के दौरान 27.65 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को अधिक से अधिक उपज देने वाली किस्मों के अधीन लोन का प्रस्ताव है। पोशक तत्वों वाली खाद की खपत को 4.47 लाख टन और तिलहन का 2.97 लाख टन किए जाने का प्रस्ताव है। गन्ने का उत्पादन 7 लाख टन और तिलहन का 11.1 प्रति टा और 13.4 प्रति टा अधिक है जो कि 1986-87 के लक्ष्यों से 11.1 प्रति टा और 13.4 प्रति टा अधिक है। इन बढ़े हुए लक्ष्यों को पूरा करने के लिये प्रति यूनिट क्षेत्र की उपज को उत्तम खेती की प्रणालियों तथा उपयोगी पदार्थों के संतुलित प्रयोग से बढ़ाने का प्रस्ताव है। विभिन्न फसलें उगाने में किसानों की तकनीकी क्षमता में सुधार का प्रस्ताव है। विभिन्न फसलें उगाने में किसानों की तकनीकी क्षमता में सुधार लाने का वि. व. बैंक के विस्तार परियोजना चरण 2 को पूरे उत्साह से लागू किया जाएगा।

भुशक खेती तथा सब्जी की फसलों को बढ़ावा देने के लिए गुडगांव, महेन्द्रगढ़ तथा भिवानी जिलों के चुने हुए खण्डों में इटली सरकार द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना को लागू किया जा रहा है जो वर्ष 1987-88 के दौरान जारी रखी जाएगी। आगामी वित्त वर्ष के दौरान फलदार, फसलों के अन्तर्गत 1000 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि लाई जाएगी जिससे कृषि उत्पादन में विविधता आएगी। इस वर्ष के दौरान हरियाणा कृषि वि विद्यालय हिसार कृषि इंजीनियरी उपाधि पाठ्यक्रम भुरू करने जा रहा है।

भाण्डागार तथा विपणन

हरियाणा भाण्डागार निगम का आगामी वित्त वर्ष के दौरान 93500 मीटरी टन की भण्डार भाक्ति बढ़ाने का प्रस्ताव है। हरियाणा भूमि सुधार तथा विकास निगम द्वारा "कल्लर" भूमि का सुधार काने के लिए 60000 मीटरी टन जिप्सम रियायती दामो पर बांटने की संभावना है। आ ता है कि हरियाणा बीज निगम 1987-88 के दौरान लगभग 1.98 लाख क्विंटल बढ़िया बीज बांटेगा। हरियाणा राज्य कृषि मार्कीटिंग बोर्ड द्वारा लगभग 48000 मीटरी टन की भण्डार क्षमता बढ़ाने और चार नई विनियमित मण्डिया, 15 प्रांगण और 15 खरीद केन्द्र विकसित करने की संभावना है।

ग्रामीण विकास

राज्य की अर्थ-व्यवस्था भूमि-प्रधान होने के कारण, ग्रामीण विकास, प्रगति की नीति का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन आगामी वर्ष के दौरान 6.74 करोड़ रुपये के खर्च करने का प्रस्ताव है। रेगिस्तान विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 में जिला भिवानी, रोहतक, हिसार तथा सिरसा में 3.1 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है। सूखे की संभावना वाले क्षेत्र संबंधी कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला महेन्द्रगढ़ में 1.36 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है। ये दोनों कार्यक्रम ही क्षेत्र-आधारित कार्यक्रम हैं जिनका उद्देश्य भूमि की उत्पादकता बढ़ाने से रेगिस्तान/सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों का समन्वित विकास करना और वहां के निवासियों को आय के सहायक साधन उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन आगामी वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार वालों/बेरोजगार के लिये 15 लाख श्रम-दिनों का कार्य पैदा करने के लिए 4.47 करोड़ रुपये के खर्च का प्रस्ताव है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अधीन लगभग 5.5 करोड़ रुपये के खर्च से 13.06 लाख श्रम दिनों का कार्य पैदा करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, मेवात क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए आगामी वर्ष के दौरान 2.5 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है।

खाद्य तथा पूर्ति

खाद्य तथा पूर्ति विभाग, हैफेड और हरियाणा भाण्डागार निगम द्वारा अनाज भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्यों पर प्राप्त किया जाता है ताकि किसानों को अपनी उपज के उचित दाम प्राप्त हों। ये एजेंसिया 1986-87 के दौरान अब तक गेहू की 23.36 लाख टन की रिकार्ड मात्रा प्राप्त कर चुकी है। वास्तव में, हम इतने अधिक अनाज की प्राप्ति को पूरा करने में सहायता प्रदान के लिये भारत सरकार, भारत रिजर्व बैंक तथा भारतीय खाद्य निगम के आभारी है।

प डुपालन

प डुओं के लिए बढ़िया स्वास्थ्य जुटाने हेतु-राज्य सरकार का 1987-88 के दौरान 30 प डु चिकित्सा तथा एक पालीक्लिनिक खोलने का प्रस्ताव है। आगामी वर्ष में, 4000 परिवारों को मुर्गी पालन, सुअर पालन, भेड़ों और बछड़ों के पालन योजना के अधीन, अनुसूचित जातियों के परिवारों को मेंढ़े तथा बढ़िया नस्ल के सुअर तथा मुफ्त प डु-चिकित्सा मुहैया करने के लिये 161.5 लाख टन दूध 23.5 करोड़ अण्डे तथा 10.5 लाख किलोग्राम ऊन के उत्पादन के लक्ष्यों का प्रस्ताव है

मछली पालन

मछली पालन का विकास खेहिर वर्ग की आय बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। वर्ष 1987-88 के लिए 165 लाख रुपये के खर्च का प्रस्ताव है। नील क्रांति की सुदृढ़ नीव रखने के

लिए इस खर्च से 350 लाख बढ़िया मछली बीज तथा 16500 टन मछली के उत्पादन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये 2.46 लाख श्रम-दिनों का रोजगार पैदा होने की संभावना है।

वन

राज्य का कम प्रति ात भूमि-क्षेत्र बनों के अधीन होने के बावजूद राज्य ने वृक्षारोपण खेतों की मेंड़ों पर पेड़ लगाने, रेल पटरियों सड़को और नहरों के साथ बंजर भूमियों के उपयों द्वारा और रेत के टीलों के स्थिरी-करण तथा बरसाती पानी के सदुपयोग द्वारा भूमि संरक्षण में प्रभाव ाली प्रगति की है। वर्ष 1987-88 के दौरान 21600 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि वनों के अधीन लाने का प्रस्ताव है। आगामी वित्त वर्ष के दौरान वृक्षारोपण और अन्य जीव परिरक्षण पर 20 करोड़ रूपए से अधिक खर्च करने का प्रस्ताव है।

सहकारिता

सहकारिता अभियान ने ऋण की व्यवस्था से लेकर अपने कार्यकलाप कृषि उत्पादन के लिए पदार्थ जुटाने प्रसंस्करण विपणन आवास तथा उद्योग तक विस्तृत करके हरियाणा के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह प्रस्ताव है कि 1987-88 के दौरान सहकारी उधार तथा सेवा सोसाइटियां 239 करोड़ रूपए के कर्जे देंगी। भवेत क्रांति को बढ़ावा देने के लिये 1987-88 के दौरान, डेरी विकास स्कीमों को

क्रियान्वित करने के लिए 108 लाख रूपए खर्च करने का प्रस्ताव हैं। इन निधियों को आप्रै 1 न फलड 2 को कार्यन्वित करने के लिए हरियाणा डेरी विकास सहकारी भूमि विकास बैंक आगामी वित्त वर्ष के दौरान 70 करोड़ रूपए तक का ऋण देगा। आगामी वर्ष के दौरान, सहकारिता आवास सोसाइटियों द्वारा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 1000 मकान बनाने का प्रस्ताव हैं। हैफेडे, जो माल्ट प्लांट की स्पिना कर रहा हैं। विपणनप एवं प्रसंस्करण सोसाइटियों द्वारा आगामी वर्ष के दौरान एक और चावल मिल लगाई जाएगी। कन्फेड द्वारा 3 करोड़ मीटरी टन की क्षमता वाली आटा मिल लगाने की संभावना हैं। वर्ष 1987-88 के सम्बन्ध में, सहकारिता विभाग के लिए 685 लाख रूपए के खर्च का प्रस्ताव हैं।

उद्योग

राज्य सरकार कृषि के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों को बढ़ाने के लिए उद्योगीकरण के लिए भरसक प्रयत्न कर रही हैं। औद्योगिक इकाइयों को दी गई बिक्री स्थगन केन्द्रीय तथा राज्य के पिछड़े क्षेत्रों वाले अंचल "क" की इकाइयों को 9 वर्ष के लिए अंचल "ख" की इकाइयों को 7 वर्ष तथा अंचल "ग" की इकाइयों को 5 वर्ष के लिए उपलब्ध होगा। अंचल "ग" फरीदाबाद तथा बल्लभगढ़ क्षेत्र शामिल होंगे। भोश क्षेत्र अंचल ख में होगा। राज्य सरकार ने जिला रोहतक तथा झज्जर तहसीलों को हाल ही में पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया है। सरकार उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों

तथा 100 प्रति शत निर्यात उन्मुखी इकाइयों को बढ़ावा भी देना चाहती हैं वर्ष 1987-88 के दौरान, ग्रामीण उद्योगीकरण स्कीम के अधीन, 4050 नई इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव है और इनसे 12150 व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा होने की संभावना है। एक तेल पोषक कारखाना करनाल में 1500 करोड़ रूपए से अधिक पूंजी खर्च से संयुक्त क्षेत्र में लगा जा रहा है। भारत इलैक्ट्रॉनिक्स पंचकूला पूंजी खर्च से संयुक्त क्षेत्र में लगाया जा रहा है। राज्य सरकार में 21 करोड़ रूपए की दूर-संचार परियोजना लगा रहा है। राज्य सरकार इलैक्ट्रॉनिक उद्योग की और विशेष ध्यान दे रही है। इस प्रयोजन के लिये 130 लाख रूपये की राशि रखने का प्रस्ताव है। सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक-क्षेत्र उपक्रमों में कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए हरद्वान द्वारा राज्य में कम्प्यूटरों का जाल बिछाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1987-88 के दौरान, उद्योग विभाग के लिए 10 करोड़ रूपए खर्च करने का प्रस्ताव है।

औद्योगिक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा

राज्य सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण तथा व्यवसायिक शिक्षा पर जोर दे रही है ताकि जनसंख्या का एक बड़ा भाग निजी रोजगार अपना सके। वर्ष 1987-88 के दौरान नए व्यवसाय आरम्भ करने, इलैक्ट्रॉनिक्स तथा अन्य व्यवसायों में अतिरिक्त सीटें जुटाने और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उपकरणों का स्तर बढ़ाने के लिए 2 करोड़ रूपए से अधिक राशि खर्च करने का

प्रस्ताव हैं। राज्य के व्यवसायिक शिक्षा संस्थान 10, 12 शिक्षा पद्धति को लागू करने में सहायता दे रहे हैं। आगामी वर्ष में 13 नए व्यवसायिक शिक्षा संस्थानों तथा एक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान के लिए 2.50 करोड़ रूपए खर्च करने का प्रस्ताव है।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, दूरस्थ आभास, ऊर्जा के गैर परम्परागत साधनों अनुसंधान तथा विकास एवं उद्मकर्ता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी-स्नातकों के लिए पथ-प्रदर्शक की भूमिका निभा रहा है। केन्द्र अहमदाबाद के सहयोग से फसल उत्पादन सम्बन्धी पूर्व-सूचना तथा उत्पन्न दूरस्थ आभास वैज्ञानिक उपयोगों के यै हिसार में स्थापित किया जा रहा है। वर्ष 1987-88 के दौरान अन्तर-सक्रिय कम्प्यूटर प्रणाली तथा हरसैक भवन निर्माण के लिए 60 लाख रूपए की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है समन्वित ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम को अगामी वित्त वर्ष के दौरान दो और खण्डों तक विस्तारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम पर 50 लाख रूपए की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है। फोटोवोल्टायक सड़क प्रकाश व्यवस्था, सौर कुकरो, फोटो बोल्टायक सिंचाई पम्प सैटो, सामुदायिक बायो-गैस संयंत्रों तथा अन्य गैर-परम्परागत ऊर्जा साधनों के प्रयोग का प्रदर्शन करने के लिए जिला सोनीपत के विधलान तथा जिला भिवानी में पालूवास नामक दो अन्य "ऊर्जा ग्रामों" को लेने का प्रस्ताव है। इन गावों पर 15 लाख रूपए की राशि खर्च की जाएगी। अगामी वर्ष के

दौरान, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, गैर परम्परागत ऊर्जा साधन विभाग, भारत सरकार, तथा हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के सहयोग से, मोती लाल नहेहरू खेल-कूद विद्यालय राई में 20 किलोवाट क्षमता वाला एक सौर फोटोवोल्टायक ऊर्जा संयंत्र लगाएगा।

पर्यावरण नियन्त्रण

उचित परिवे 1 संबंधी सन्तुलन बनाए रखने को महत्व देते हुए, 1984 में राज्य में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई। जल बोर्ड तथा भूमि उपयोग बोर्ड इस विभाग के प्रासासनिक नियंत्रण में हैं। वर्ष 1987-88 के दौरान पर्यावरण के लिए 90 लाख रूपए रखने का प्रस्ताव है।

सड़के

हरियाणा में योजक सड़को का महत्वपूर्ण जाल बिछा हुआ है जिनसे प्रत्येक गांव मुख्य सड़को से जुड़ा हुआ है। वर्ष 1987-88 के दौरान नई सड़के बनाने के लिए 5.2 करोड़ रूपए खर्च करने का प्रस्ताव है। कुरुक्षेत्र और करनाल में सड़क उपरिपुलों के पूरे होने की सम्भावना है। करनाल और मेरठ को मिलाने वाले यमुना नदि पर एक बड़े पुल की मंजूरी भारत सरकार द्वारा दे दी गई है और मुख्य मंत्री द्वारा हाल ही में उसकी नीव रखी गई है। भारत सरकार ने लगभग 40.16 करोड़ रूपए के अनुमानित खर्च पर सुरथल से करनाल तक भोर 16 सूरी मार्ग

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० १ को चार लाइनों वाला बनाने की योजना को भी अन्तिम रूप से मंजूरी दे दी है। इसके अतिरिक्त वि व बैको मि ान टीम ने फरवरी, 1987 में राज्य का दौरा किया और वह भोर ाह सूरी मार्ग को 130 कि०मी० से 212.16 कि०मी० हरियाणा/पंजाब सीमा सीमा तक चार लाइनों वाला बनाने का काम पूरा करने की सिफारि ा करने के लिए सहमत हो गई है।

परिवहन

हरियाणा परिवहन दे ा में सबसे अग्रणी परिवहन उपक्रमों में से एक हैं। यह प्रतिदिन 11 लाख यात्री उठाता हैं और 9 लाख कि०मी० से अधिक दूरी तय करता है। वर्ष 1987-88 के दौरान इस पर 13 करोड़ रूपये के खर्च का प्रस्ताव हैं। इसमें से 322 बसे ंबदलने के लिए 10.47 करोड़ रूपए खर्च करने का प्रस्ताव हैं।

आधुनिक नए बस कर्म ालाएं तथा पंक्ति आश्रय-सलिल बनाने पर 1.8 करोड़ रूपये की राि ा खर्च होने की संभावना हैं। अगामी वर्ष के दौरान कर्म ालाओं के आधुनिकीकरण के लिए 30 लाख रूपए का प्रस्ताव हैं। अगले वर्ष 10 लाख रूपये की लागत से एक नई कम्प्यूटरीकरण स्कीम आरम्भ करने की योजना है। पुलिस विभाग, हरियाणा के अराजपत्रित कर्मचारियों को केवल 20 रूपये प्रतिमास के नाममात्र भुगतान पर प्रथम जनवरी, 1987 से हरियाणा परिवहन की बसों में यात्रा करने की अनुमति दी गई हैं।

शिक्षा

राज्य सरकार मानव संसाधन विकास की सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाने के उद्देश्य से, 1987-88 के दौरान मुख्य रूप से लड़कियों के लिए 100 नए प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। वर्ष 1987-88 के दौरान 94 विद्यालय भवन और 18 रिहायशी क्वार्टर पूरे करने के लिए 160 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1987-88 के दौरान, 100 प्राथमिक विद्यालयों का दर्जा बढ़ाकर मिडल विद्यालय, 50 मिडल विद्यालयों उच्च विद्यालयों का दर्जा बढ़ाकर मिडल विद्यालय, 50 मिडल विद्यालयों का दर्जा बढ़ाकर उच्च विद्यालय तथा 25 उच्च विद्यालयों का दर्जा बढ़ाकर सीनियर माध्यमिक विद्यालय 10 व 12 प्रणाली बनाने का प्रस्ताव है। 2.26 लाख प्रौढ़ों को अक्षर-ज्ञान देने के लिए अगले वर्ष के दौरान प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए, अगले वर्ष दो जिला शिक्षा संस्थान आरम्भ करने की सम्भावना है और ग्रामीण क्षेत्रों में छः नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में, एक और राजकीय महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय शिक्षा योजना तथा प्रासासन संस्थान द्वारा स्वायत्त महाविद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए द्रोणाचार्य राजकीय महाविद्यालय, गुडगांव को आदर्श महाविद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए द्रोणाचार्य राजकीय महाविद्यालय, गुडगांव को आदर्श महाविद्यालय के रूप में

अपनाया गया है। उप मण्डलीय स्तर पर तीन और पुस्तकालय खोलने का विचार है। प्राइवेट महाविद्यालयों का 95 प्रतिशत खर्च राज्य द्वारा अनुदान के रूप में पहले ही पूरा किया जा रहा है। अब राज्य सरकार ने प्रथम दिसम्बर, 1985 से राज्य में विविद्यालयों तथा राजकीय और प्राइवेट महाविद्यालयों के शिक्षण अमले को अन्तरिम राहत की दो किंतां भी मजूर की है। वर्ष 1987-88 के दौरान उर्दू को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा उर्दू अकादमी को 10 लाख रूपए का अनुदान देने का प्रस्ताव है। इस प्रकार राज्य सरकार राज्य में शिक्षा के प्रचार के लिए व्यापक नीति अपना रही है।

स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा

राज्य में विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुधार के लिए सरकार निरन्तर प्रयत्न कर रही है। इस उद्देश्य हेतु 1987-88 के दौरान 150 उपकेन्द्र 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। चार और जिलों को व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अधीन लाने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार ने हाल ही में 1985-86 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम में सर्वोत्तम कार्य के लिए 2.5 करोड़ रूपए का नकद पुरस्कार प्राप्त किया है। कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन एक नमूना सर्वेक्षण एवं निर्धारण यूनिट स्थापित करने का

प्रस्ताव है। वर्ष 1987-88 के दौरान स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा के लिए 12.13 करोड़ रूपए खर्च करने का प्रस्ताव है।

सरकार, राज्य के लोगों को अत्यधिक उन्नत चिकित्सा सुविधाएं देने का भरसक प्रयत्न कर रही हैं। इस उद्देश्य से सरकार ने मैडिकल कालेज, रोहतक में सुधार लोन को अउच्च प्राथमिकता दी है, जिसे अब दर्जा बढ़ाकर स्नातकोत्तर संस्थान के स्तर का बना दिया गया है। उच्च कोटि के डाक्टरों को अकर्षित करने के लिए, उसके संकाय के सदस्यों के वेतन मान पी० जी० आई०, चण्डीगढ़ के सदस्यों के बराबर कर दिए गए हैं। कार्डियोलॉजी कार्डियक सर्जरी, गैस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी विभाग आरम्भ कर दिए गए हैं और अगले वर्ष से उनके कार्य आरंभ कर देने की संभावना है। कैसर की चिकित्सा के लिए सम्पूर्ण भारीर के कैट स्कैन तथा कोबाल्ट थेरापी यूनिट जैसे परिष्कृत उपकरण प्राप्त करने का प्रस्ताव है। आगामी वित्त वर्ष के दौरान महाविद्यालय में विकीरण चिकित्सा में एम० डी० और मनोरोगविज्ञान में विकीरण चिकित्सा में एम० डी० और मनोरोगविज्ञान में एम० डी० आरम्भ होने की भी संभावना है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने की दृष्टि से 1987-88 के दौरान 30 लाख रूपए खर्च करने का प्रस्ताव है। आगामी वर्ष के दौरान 20 नए आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने की संभावना है।

तकनीकी शिक्षा

मानव संसाधन विकास के लिए राज्य की नीति में तकनीकी शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। आता है कि 1987-88 के दौरान मुरथल में नया राज्य इंजीनियरिंग महाविद्यालय अपने प्रांगण में नियमित शिक्षण कक्षाएं आरम्भ कर देगा। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम वाले बहुत से नए संस्थान जैसे राजकीय महिला बहु-तकनीकी, सिरसा राजकीय प्रबन्ध तथा फार्मैसी संस्थान आदमपुर और अस्पताल इंजिनियरिंग संस्थान रोहतक को अगामी वित्त वर्ष के दौरान और विकसित करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1987-88 के दौरान तकनीकी शिक्षा पर 4.5 करोड़ रूपए खर्च करने की सम्भावना है।

जन-स्वास्थ्य

वर्ष 1987-88 के दौरान 330 समस्या गांवों तथा अन्य 20 गांवों में जल सप्लाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए, राज्य योजना के अधीन 25.74 करोड़ रूपए के खर्च का प्रस्ताव है। भारत सरकार की ओर से परिवर्धित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम (Accelerated Rural Water Supply Programme) के अधीन 5.2 करोड़ रूपए की व्यवस्था कराने की संभावना है और इसके अन्तर्गत 110 अतिरिक्त समस्या गांवों को पानी पहुंचाने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त आगामी वित्त वर्ष के दौरान भाहरी

क्षेत्रों में जल सप्लाई तथा निकास सुविधाओं में सुधार करने के लिए 7.12 करोड़ रूपए की राशि का प्रस्ताव है।

आवास और नगरीय विकास

आवास बोर्ड, हरियाणा ने अब तक 25000 से अधिक मकानों का निर्माण किया है जिनमें से 19000 से अधिक निम्न वर्ग तथा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए है। बोर्ड, किराया स्कीम के अधीन मेवात क्षेत्र में पुलिस कर्मचारियों तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण कर रहा है। वर्ष 1987-88 के दौरान बोर्ड ने 3000 मकान बनाने का प्रस्ताव किया जिनमें से 2000 मकान निम्न आय वर्ग (LIG) समाज के आर्थिक रूप से कमजारे वर्ग के लिए होंगे। योजनाबद्ध भाहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा भाहरी विकास प्राधिकरण वाणिज्यिक और औद्योगिक प्लॉटों के लिए 4000 एकड़ भूमि अर्जित करने तथा विकास शुरू करने की योजना है।

स्थानीय स्वायत्त भासन

स्थानीय निकाय विभाग, भाहरी क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाएं जुटाने के लिए विभिन्न नगरपालिका समितियों के कार्य में तालमेल लाना चाहता है वर्ष 1987-88 के दौरान इस विभाग के लिए लगभग 2 करोड़ रूपए का खर्च प्रस्तावित है। यह खर्च मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अधीन जल निकाय तथा मल निकास संकर्मों, कम लागत के सफाई संकर्मों,

भाहरी गन्दी बस्तियों के सुधार तथा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को सहायता-प्रदान देने के लिए प्रयोग में लाया जाना प्रस्तावित है।

हरियाणा में पर्यटन, आर्थिक समृद्धि की ओर हमारे साहसिक, कदम को लाकप्रकय बनाने में एक अग्रदूत की भूमिका निभा रहा है। इस भूमिका के अनुसरण में तैराकी सरोवरण सम्मेलन भवन तथा एम्पोरियमों से युक्त किंगफि 18 पर्यटक कम्पलैक्स, अम्बाला का हाल ही में मुख्य मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया है। बड़खल फरीदाबाद तथा मैना पर्यटन कम्पलैक्स के साथ रिहाय गी स्थान जोड़ दिए गए हैं। कुरुक्षेत्र में 100 बिस्तरों वाला एक यात्री निवास, मैगपाई में रिहाय गी स्थान और पिपली में युवा होस्टल का निर्माण हो रहा है। सूरजकुंड (फरीदाबाद) में गॉल्फ के मैदान के विस्तार तथा दमदमा (करनाल) और धारूहेड़ा में पर्यटन कम्पलैक्सों के विस्तार तथा दमदमा (गुडगांव) पर्यटक कम्पलैक्स के विकास के लिए भसरत सरकार द्वारा धन स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार हरियाणा, सुसज्जित पर्यटक रिहाय गी की व्यवस्था करने के लिए प्रयत्न गील हैं जिसमें तुलनात्मक रूप से सस्ती दरों पर आधुनिक मनोरंजन सुविधाए उपलब्ध हो। राज्य सरकार ने हरियाण में पर्यटन को उद्योग घोशित किया है ताकि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच स्वथ्थ मुकाबले को बढ़ावा मिले। वर्ष 1987-88 के दौरान पर्यटन पर 1.5 करोड़ रुपये की राशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है।

संस्थागत वित्त

संस्थागत वित्त (Institutional Finance) तथा उधार नियंत्रण विभाग, हरियाण में वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य मियादी उधार दानले वाली संस्थाओं द्वारा उधार की व्यवस्था की देखभाल करता है। राज्य सरकार ने वाणिज्यिक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की नई भागाएँ खोलने के लिए राज्य में 252 केन्द्र चुने हैं और लाइसेंस देने के लिए उनकी भारतीय रिजर्व बैंक के पास सिफारिश की है। गरीब से गरीब व्यक्तियों को रिययती ब्याज की दर पर उधार देने का कार्य एक प्रतिगत के राष्ट्रीय लक्ष्य के मूकाबले में चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य में 1.87 प्रतिगत स्तर तक पहुंच गया है। इस विभाग का 1987-88 के दौरान भारत सरकार के सहयोग से हरियाणा में स्वतन्त्रता उद्यम कर्मकौशल विकास केन्द्र (Center for Enterepreneursheip Development) स्थापित करने का प्रस्ताव है।

श्रम तथा रोजगार

राज्य सरकार मजदूरों तथा मालिकों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना चाहती है। समूचे तौर पर श्रम विकास विभाग ने चालू वित्त वर्ष के दौरान इस उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। हरियाणा में अकुशल औद्योगिक मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 440.50 रूपए प्रतिमास या 16.87 रूपए प्रतिदिन है। यह हवभाग राज्य के खेती मजदूरों को औद्योगिक मजदूरों से एक रूपया प्रतिदिन अधिक दिलाना चाहता है। इस प्रकार, राज्य में न्यूनतम मजदूरी पंजाब को छोड़कर, इस क्षेत्र में

अधिकतम हैं। आगामी वित्त वर्ष में शिक्षा केन्द्र सहित एक श्रम कल्याण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त 1987-88 के दौरान एक रोजगार केन्द्र के कामकाज को कम्प्यूटर से किए जाने की संभावना है।

समाज कल्याण

राज्य सरकार समाज की अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, विमुक्त जातियों और अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण को अधिक प्राथमिकता देती है। यह उनको छोटी आयु से ही शिक्षा के लिए विशेष प्रोत्साहन देकर उनके विकास की देखभाल करती है तथा उसके पचास प्रतिशत प्रतिपाक्षण और सहायता देती है ताकि उन्हें अच्छी नौकरियों मिल जाएं या वे निजी रोजगार अपना सकें। मुफ्त लेखन-सामग्री, मुफ्त-वर्दिया, मैट्रिक से पहले तथा बाद के स्तरों पर छात्र-वृत्तियां, शिक्षण फीस की भसरपाई, मिउलती उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर पुस्तक अनुदान तथा अनुसूचित जातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के बच्चों को विशेष शिक्षण के रूप में बहुत से लाभ दिए जाते हैं। इन प्रोत्साहनों से लाभ उठाने वाल विद्यार्थियों की इस समय 2.04 लाख की संख्या बढ़कर वर्ष 1987-88 के दौरान 2.96 लाख हो जाएगी। निजी रोजगार अवसरों की व्यवथा द्वारा समाज के इन वर्गों की वित्तीय स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए, हरियाणा हरिजन कल्याण निगम, हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम तथा हरियाणा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा महिला कल्याण निगम महत्वपनूर्ण भूमिका

निभ्ला रहे हैं चालू वर्ष के दौरान हरियाणा हरिजन कल्याण निगम तथा हरियाणा पिछड़े वर्गों के 4000 लाभ-ग्रहियों को सहायता प्रदान कर चुके हैं। अनुसूचित जातियों से संबंधित विधवाओं की और असहाय तथा विकलांग स्त्रियों की पुत्रियों के विवाह खर्चों को पूरा करने के लिए 2500 रूपए की सहायता जुटाने की नई स्कीम आगामी वर्ष से भुरू किए जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1987-88 के दौरान अनुसूचित जातियों पिछड़े वर्गों तथा विमुक्त जातियों पर योजना, गैर-योजना तथा केन्द्र संचालित स्कीमों के अधीन 10.96 करोड़ रूपए की राशि खर्च किये जाने का प्रस्ताव है।

राज्य सरकार, स्त्रियों तथा बच्चों, वृद्धि तथा अशक्त व्यक्तियों और भारीरुप से विकलांग तथा असहायों के लिए कल्याण स्कीमों पर भी अधिक बल दे रही है। समन्वित बाल विकास सेवा स्कीम में अनुपूरक पोषण प्रतिरक्षण स्वास्थ्य जांच निर्देश सेवाएं पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा और पूर्व-विधालय शिक्षा की समन्वित रीति में अनेक सेवाओं की व्यवस्था की गई है। इस समय राज्य में 40 ग्रामीण तथा 5 भाहरी समन्वित बाल विकास सेवा परियोजनाए हैं। राज्य सरकार का आगामी वित्त वर्ष के अन्त तक राज्य के 97 ग्रामीण खण्डों में समन्वित बाल विकास परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार हरियाणा ग्रामीण क्षेत्रों को लगभग व्यापक रूप से समन्वित बाल विकास सेवा के अधीन लाने में देश भर में प्रथम राज्य होने की

विनिशुतता प्ररुत कर लेगा। वरुश 1987-88 के दुरररन सडनुवत डरल वरकरस सेवर सुकीड के लिए 794800 लरड-गुरहियों कर लकुषु नरयत कुरे करने कर प्रसुतरव हैं। अनरथुं तथर असहरय डरुं को 30 रुरडु प्रतुरडरस की वरतुतुीय सहरयतर डी करती हैं वरुश 1986-87 के दुरररन 5475 लरड-गुरहियों को इसके अनुतरगत लरए करने की संडरवणर हैं। वरुश 1987-88 के दुरररन 1000 अतुरररकुत लरड गुरहियों के अनुतरगत लरए करने कर प्रसुतरव हैं। आगरडी वरुश के दुरररन , डरंओ अडुर करडकरकी डहलर हरसुतल डुरे कुरे ओन कर प्रसुतरव है। असहरय सुतुररुतुीय तथर वरधवरओ को 50 रुरडु प्रतुरडरस की वरतुतुीय सहरयतर डी करती हैं वरुश 1986-87 के दुरररन 1000 अतुरररकुत लरड-गुरहियों को इसके अनुतरगत लरए करने कर प्रसुतरव हैं। सडररओक सुरकुषु सुकीड के अधीन 49000 वृदुध तथर असहरय डुरुश तथर डहलर लरड-गुरहियों को आगरडी वरुश के दुरररन 60 रुरडु प्रडररस डें डन डुरे करने की संडरवणर हैं। वरुश 1987-88 के दुरररन सडररओ कलुडरण के लिए 965 लरख रुरडु कर ओओनर खरुओ कुरे करने कर प्रसुतरव हैं।

(16.00 डओे)

ररओ सरकर डरखुडे वरुओ के सदसुतुीय के वरकरस को डुदरवर डेने के लिए उनुहें अनेक रररररतुं डेनर करहती हैं। डह प्रसुतरवत कुररर गडर हैं कुरे ओहर कुररसी गुररड सडरर कुषुतुर डें डरखुडे वरुओ के सदसुतुीय की संखुडर 2 प्रतुर डत डर अधरक हर, वहरं इन वरुओ से संडुंधरत एक डंओ ओुनरव डर नरडओदगी दुररर नररुओकुत कुररर

जाएगा। इस प्रयोजन के लिए पंजाब ग्रा पंचायत अधिनियम, 1952 को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा रहा है। इसी प्रकार यदि पिछड़े वर्गों को कोई सदस्य पंचायत समिति में नहीं चुना जाता, तो पंचायत समिति पिछड़े वर्गों में से एक सदस्य को सहयोजित करेगी। इस प्रयोजन के लिए पंजाब पंचायत समिति अधिनियम, 1961 को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सरकार ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि ऐसी भूमि का 10 प्रतिशत, जो ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे पर दिया जाता है, पिछड़े वर्गों के सदस्यों को पट्टे पर देने के लिए आरक्षित रखा जाए। यह भी प्रस्तावित किया गया है कि ऐसे गांव में जहाँ पिछड़े वर्गों के सदस्यों से संबंधित घरों की संख्या 50 या उससे अधिक हो, वहाँ पर पिछड़े वर्गों का एक सदस्य लम्बरदार नियुक्त किया जाए। इसके अतिरिक्त सरकार का वर्ष 1987-88 के दौरान पिछड़े वर्गों के लिए 100 चौपालें बनाने का भी प्रस्ताव है।

खेलकूद

राज्य सरकार राज्य में खेल-कूद के विकास की ओर विशेष ध्यान दे रही है। चालू वर्ष के दौरान फरीदाबाद में 30000 वर्ग मीटर के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया गया है। मोतीलाल नेहरू खेलकूद विद्यालय राई के विद्यार्थियों ने ऐथलेटिक्स, जिम्नास्टिक तथा तैरती में राष्ट्रीय जूनियर स्तर पर लाखों रूपए की राशि रखने का प्रस्ताव है। हरियाणा के पहलावानों, ऐथलीटों तथा बालीवाल खिलाड़ियों ने

सियोल, दक्षिणी कोरियो में, 10 वे एशियाई खेलों में छ राज्य की प्रतिष्ठा का चार चांद लगा दिए।

प्राकृतिक अपदाओं के लिए राहत

वर्ष 1986 के पतझड़ मौसम में राज्य को विशेषकर जिला हसियार, भवानी महेन्द्रगढ़, गुडगांव रोहतक, फरीदाबाद तथा सोनीपत में, अत्यन्त सूखे का सामना करना पड़ा। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा तुरन्त उपाय किए गए। सूखाग्रस्त क्षेत्रों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा तुरन्त उपाय किए गए। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भूमि जोत कर, आबियानप तकाबी तथा सहकारी ऋणों जैसी सरकारी देय राशि की वसूल निलम्बित कर दी गई भारत सरकार ने तत्काल राहत उपाय करने के लिए 17.25 करोड़ की सहायता अतिरिक्त सहायता स्वीकृत की हैं। सड़कों के निर्माण, नहरों से गाद निकालने और अन्य सम्बद्ध निर्माण कार्यों का आरम्भ करके नए रोजगार अवसर पैदा करने पर 3.96 करोड़ रूपए की राशि खर्च की जा रही हैं रासायनिक खाद की सबसिडी देने के लिए 2.5 करोड़ रूपए और बीज सबसिडी तथा बीज तकावी के लिए 1.5 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं। चारे की कमी को पूरा करने के लिए चारा-तकावी बांटी जा रही हैं और इस प्रकार दी गई राशि का 25 प्रतिशत चारा सबसिडी के रूप में दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल सप्लाई स्कीमों की वृद्धि के लिए 1.16 करोड़ रूपए खर्च किए जा रहे हैं जिनमें 100 नए नलकूपों खोदना भी शामिल हैं। दूध पलाने वाली माताओं

और 6 वर्ष की आयु से कम के बच्चों को अनुपूरक पोशाहार देने के लिए 73.73 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है। पुरुषों के लिए पीने का पानी जुटाने के वास्ते 14 लाख रुपए की राशि प्रयोग में लाई जा रही है इस प्रकार, सूखा ग्रस्त लोगों के कष्ट दूर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। वर्ष 1987-88 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राहत उपाय करने के लिए 4.5 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव है।

विकेन्द्रित आयोजना

राज्य लोगों की अनुभूत आवश्यकताओं का निर्धारण करने में विकेन्द्रित आयोजना के प्रभाव गहरी महत्व को समझता है। आयोजना को नीचे के स्तर तक ले जाने के लिए 1987-88 के दौरान 6 करोड़ रुपए की राशि रखे जाने का प्रस्ताव है। इस राशि का 20 प्रतिशत हरिजन बस्तियों के विकास -क्रियाकलापों और हरिजन-चौपालों के निर्माण पर खर्च किए जाने का प्रस्ताव है तथा अन्य 20 प्रतिशत ऐसी भाहरी गन्दी बस्तियों में सुधार लाने के लिए प्रस्तावित है जिनमें अनुसूचित जातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के लोग रहते हैं। इस प्रकार आयोजना प्रक्रिया को निर्धनो के द्वारा तक पहुंचाया जा रहा है।

1986-87 के लिए संशोधित अनुमान

वर्ष 1986-87 के सं गोधित अनुमानों के अनुसार, बजट में अल्लिखित 0.41 करोड़ रूपए के घाटे की बजाए चालू वित्त वर्ष के अन्त में 45.2 करोड़ रूपए के घाटे की संभावना है। घाटे में वृद्धि का मुख्य कारण योजना खर्च में बढ़ती हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा कम साणन जुटा पना और गैर योजना खर्च में बढ़ोत्तरी हैं। भारत सरकार से प्राप्त अतिरिक्त केन्द्रीय योजना सहायता के कारणर, वर्ष के लिए सं गोधित योजना खर्च 525 करोड़ रूपए के मूल आंकड़ो कके मुकाबले में बढ़ाकर 569.62 करोड़ रूपए कर दिया गया हैं। योजना-खर्च में यह वृद्धि विकास की गति को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

1987-88 के बजट अनुमान वार्षिक योजना

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस गरिमा ाली सदन के सामने 1987-88 के लिए हरियाणा सरकार के बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूं। निम्नलिखित तालिका में 1986-87 के सं गोधित अनुमानों तथा 1987-88 के बजट अनुमानों के फलस्वरूप राज्य की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण दिया गया हैं:-

संघटक	बजट अनुमान 1986-87	सं गोधित अनुमान 1986-87	बजट अनुमान 1987-88
(1) प्रारंभिक			

भोश (Opening Balance)			
(क) महालेखाकर के अनुसार	(+) 43.01	(-) 31.81	(-) 81.87
(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार	(-) 0.41	(+) 4.86	(-)45.20
(2) राजस्व लेखा:-			
(i) प्राप्तियां	1040.14	1069.22	1275.07
(ii) खर्च	907.16	979.03	1084.34
(iii) अधि शेष	(+) 132.98	(+)90.19	190.73
(3) पूंजीगत खर्च (निबल)	186.65	210.78	184.76
(4) सार्वजनिक ऋण (Public Debt):-			

(i) उपगत ऋण (Debt Incurted)	749.10	721.78	184.76
(ii) वापसी भुगतान (Repayment)	629.71	505.12	464.96
निबल	(+) 122.39	(+)216.71	132.52
(5) कर्ज तथा पे ि टया:-			
(i) पे ि टगियां	166.45	246.55	236.68
(ii) वसूलियां	30.40	25.86	35.43
निबल	(-)136.05	(-)220.69	(-)201.25
(6) लोक लेखा (Public Account):-			
(i) अनिधिक ऋण (unfunded	(+)37.41	(+)37.91	(+)40.08

Debr)			
(ii) निक्षेप (deposits) पे ागिया तथा अन्य निबल	(+)2.29	26.10	22.75
(iii) प्रेशण (Remittances)	(+)1.00	(+)74.51	(+)73.33
निबल	(+)40.60	(+)74.51	(+)73.33
(7) वर्ष का अन्तिम भोश (Closing Balance)			
(क) महालेखाकार के अनुसार	(+)16.28	(-)81.87	(-)73.33
(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार	(-) 27.17	(-)45.20	(-)34.63

मैं, अब पूर्वोक्त अनुमानों तथा 1987-88 की बजट व्यवस्थाओं के मुख्य लक्षणों का उल्लेख करूंगा। प्रारंभिक बजट अनुमानों के अनुसार बजट में राजस्व प्राप्तियों की 104014 करोड़ रूपए की व्यवस्था थी।

अब यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार क अथक प्रयासों के कारण, राजस्व प्राप्तियों के चालू वर्ष की समाप्ति तक 1069.22 करोड़ रूपए तक पहुंचने की संभावना हैं। इसके अतिरिक्त 1986-87 के सं गोधित अनुमानों में 90.19 करोड़ रूपए राजस्व सरपलस होने की संभावना हैं जोकि 1987-88 में 34.63 करोड़ रूपए का दिखाया गया घाटा, गैर-योजना खर्च में किफायत तथा कर राजस्व की बेहतर वसूली द्वारा पूरा किया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घोशणा करना मेरे लिए बड़े गर्व का विशय है कि इस बजट में समाज के किसी भी वर्ग पर कोई नया कर भार नहीं डाला जा रहा हैं।

यह अत्यधिक संतोश की बात हैं कि 1987-88 के दौरान हमारी योजना लागत 585.75 करोड़ रूपए निर्धारित की गई हैं। बिजली क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि प्रस्तावित की गई हैं। बिजली योजना खर्च 1986-87 में 166.69 करोड़ रूपए से 1987-88 में 195.04 करोड़ रूपए तक होना संभावित हैं जो कि लगभग 17 प्रति ात वृद्धि द ार्ता हैं। इसके अतिरिक्त, विकास में मानव संसाधनों के अत्यधिक महत्व को ध्यान मं रखत हुए, सामाजिक

सेवाओं पर खर्च 1986-87 में 92.82 करोड़ रूपए से 1987-88 में 113.23 करोड़ रूपए तक लाकर लगभग 22 प्रति शत बढ़ाने का प्रस्ताव है। मूझे वि वास है कि मेरे सभी साथियों के सहयोग तथा हमारे मुख्य मंत्री के गति िल नेतृत्व से आने वाले वर्ष में योजना तथा गैर योजना खर्च के बीच अधिक अनुकूल अनुपात संभव हो जाएगा।

किसानों को कर रियायतें

राज्य सरकार ने खालों को पक्का करने के खर्च की वसूली के लिए 113 करोड़ रूपए की राशि माफ करने का फेसला किया है। इससे कृषि का खर्च कम हो जाएगा और यह हरियाणा के किसानों के लिए वरदान सिद्ध होगा।

राज्य सरकार ने राज्य में भू-राजस्व/भूमि जोत कर 15 नवम्बर, 1986 को देय होने वाली किस्त से समाप्त करने का फेसला किया है। इस फेसले के फलस्वरूप, लगभग 5.75 लाख भू-स्वामियों को लाभ होगा।

व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को रियायते

राज्य सरकार, व्यापार तथा उद्योग की उचित मांगों के प्रति जागरूक है और उन्हें बहुत सी रियायते दी जानी हैं। राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि 1000 सी0 सी0 तक की इंजन क्षमता वाली ईंधन कु ाल गाड़ियों पर सामान्य बिक्री कर 10 प्रति शत से घटाकर 6 प्रति शत कर दिया जाए जैसा कि पहले

ईधन कु ाल कारों के मामले में किया गया था। इसी प्रकार ईधन-कु ाल जिप्सी जीपों पर सामान्य बिक्री कर घटाकर 3 प्रति ात किया गया है। इसके अतिरिक्त ईधन कु ाल कारों और गाड़ियों पर अन्तर राज्य आधार पर हरियाणा से बाहर बिक्री करने के लिए सहमत हो गया है और इससे 10 करोड़ रूपए प्रतिवर्ष अतिरिक्त कर प्राप्त होने की आ ा है। अन्य मुख्य रियायतों में प्रमाणित बीजों पर कर की दर 8 प्रति ात से घटाकर 2 प्रति ात किया गया है। इसके अतिरिक्त, गेहूं के चोकर, चना छिलका तथा अजवायन के बीजों को बिक्री कर से छूट दे दी गई है चूड़ियों पर भी बिक्री कर माफ कर दिया गया है। सिले-सिलाए वस्त्रो पर 4 प्रति ात का समान बिक्री कर लगाया है चाहे उनकी लागत कुछ भी हो। टाइप म िनों पर बिक्री कर 12 प्रति ात से घटाकर 10 प्रति ात कर दिया गया है। लौह तथा अलौह धातुओं के व्यापारियों को अन्तर्राज्यिक बिक्री के संबंध में सी फार्म के बिना पहले से उपलब्ध 4 प्रति ात की दर से रियायत को अब पहली अप्रैल, 1987 से 31 मार्च, 1988 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त विक्रय कर की विवरणियां प्रस्तुत करने तथा उसके निर्धारण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। राज्य सरकार ने व्यापारी वर्ग को एक बड़ी राहत के रूप में उनके द्वारा छपवाए गए अपने निजी बिक्री कर फार्म संख्या 13,14 तथा 15 का प्रयोग करने की भी अनुमति दे दी है। इसके अतिरिक्त यह भी फेसला किया गया है कि व्यापारी वर्ग से निकट सम्पर्क बनाए रखने और बिक्री कर के ढांचे को सरल और

युक्तियुक्त बनाने के तरीकों की जांच के लिए एक परामर्श-बोर्ड बनाया जाए। इसके अतिरिक्त, संक्षिप्त निर्धारण प्रक्रिया दुकानदारों पर भी लागू की गई हैं चाहे उनके आवर्त की मात्रा कुछ भी हो, परन्तु भारत यह है कि निर्धारित पिछले वर्ष की विवरणियों की तुलना में कम से कम 15 से 20 प्रतिशत अधिक कर वृद्धि दी जाए। इस प्रकार प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने, संपर्क बढ़ाने तथा राज्य के व्यापारियों और उद्योगपतियों को बहुमूल्य कर राहत देने के लिए कदम उठाए गए हैं।

सेवा निवृत्त और कार्यरत कर्मचारियों को रियायतें

राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सदा ही उदार दृष्टिकोण अपनाया है। पिछले बजट भाषण में दिए गए इस आवासन के अनुसार कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे की चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के प्रकार में जांच करना चाहती है, राज्य सरकार द्वारा घोषित संशोधित वेतनमान हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए भी पहली जनवरी, 1986 से लागू किए जाए। वेतनमानों में संशोधन के फलस्वरूप पहली जनवरी, 1986 से 31 मार्च 1987 तक का बकाया कर्मचारियों के सामान्य निधि खातों में जमा कर दिया जाएगा। संशोधित वेतनमान निर्दिष्ट करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अच्च स्तरीय समिति नियुक्त की गई है।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने पहले ही प्रथम अप्रैल, 1979 से पूर्व पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए 24 सितम्बर, 1985 को, भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर, पेंशन फार्मूले को दासद बना दिया था। इस उदार फार्मूले के परिणामस्वरूप, उन सेवा-निवृत्त व्यक्तियों को पेंशन पर जिलकी सेवानिवृत्ति के समय औसत परिलब्धिया (Emoluments) 900 रु. में थी, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस कठिनाई को दूर करने के लिए, राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त व्यक्तियों को 24 सितम्बर, 1985 के आदेशों के आधार पर अपनी पेंशन प्राप्त करने हेतु विकल्प देने का निर्णय किया है।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को विकल्प देने का निर्णय किया है कि वे या तो 150 रूपए वार्षिक का नियत चिकित्सा भत्ता ले लें या प्रतिपूर्ति (Provision) के आधार पर बहिरंग मुफ्त चिकित्सा उपचार सुविधा प्राप्त करना जारी रखें, जैसा कि यह पहली मार्च, 1986 से पूर्व विद्यमान थी। इससे राज्य के खजाने पर 91 लाख रूपए का अतिरिक्त भार पड़ने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने सरकार ने कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि में अपनी जमा राशियों पर ब्याज की दर पहली अप्रैल, 1986 से 9 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत करके अधिक बचत के लिए प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है। इससे राज्य के खजाने पर 7.95 करोड़ रूपए का अतिरिक्त भार

पड़ने की संभावना है। इस प्रकार राज्य सरकार ने कर्मचारियों का कुशलता स्तर बढ़ाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए हैं।

अर्थोपाय स्थिति

खर्च में अधिक वित्तीय अनुपासन तथा औचित्य लाने के उद्देश्य से, केन्द्रीय सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने ओवर-ड्राफ्ट की वह सुविधा वापस ले ली है जिसका उपयोग राज्यों द्वारा अपने आकस्मिक दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जाता था। विकास की आवश्यकताओं के कारण हम पर लगाई गई कठोर सीमाओं के बावजूद, हमने सारा साल अपनी अर्थोपाय स्थिति को सफलतापूर्वक व्यवस्थित किया है। राज्य में उन्नति की गति को तेज करने के लिए वित्तीय देखभाल की प्रक्रिया को अधिक सुचारु बनाया जा रहा है।

भाषण समाप्त करने से पूर्व, मैं वित्त विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिन्होंने इन अनुमानों को तैयार करने में बहुमूल्य सहायता दी है। मैं इस संबंध में सहायता देने के लिए महालेखाकार हरियाणा का तथा दस्तावेजों को समय पर छापने के लिए संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन तथा हरियाणा मृद्रणालय का भी आभारी हूँ।

महोदय, इन भाव्दों के साथ अब मैं वर्ष 1987-88 के बजट अनुमान इस गरिमा ाली सदन के विचार तथा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करता हूँ।

जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: अब हाउस कल प्रातः 9.30 बजे तक के लिए ऐडजर्न किया जाता है।

(16.09 बजे)

(तत्प चात् सदन मंगलवार, दिनांक 3-3-1987 को प्रातः 9.30 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।)